साप्ताहिक
शहर सत्ता
PRGI NO. CTHIN/25/A2378
सोमवार, 29 दिसंबर से 04 जनवरी 2025
हम दिखाएंगे आईना...

पेज 04 में...
साय के सुशासन में अब नहीं दबेंगी जनहित की फाइलें

पेज 12 में...
गरीबों की जेब में डाका ?

वर्ष : 01 अंक : 43 पृष्ठ : 12 मूल्य : 5 रुपए www.shaharsatta.com

पेज 03 भाजयुमो ने जलाया पूर्व सीएम भूपेश बघेल का पुतला

फ़िज़ा में कौन घोल रहा है ज़हर...?

जिन्हें पुलिस ने संदिग्ध रोहिंग्या, बांग्लादेशी समझा वो निकले हज यात्री

ठिठुरा देने वाले सर्द मौसम में गर्म बिस्तर में गहरी नींद में जब रायपुर की मुस्लिम जमात के युवा, बुजुर्ग महिला-पुरुष और शहर की नामचीन शख्सियत को गैर जिम्मेदाराना तरीके से खाखी का रुआब दिखाते हुए लेकर चले जाना अल्पसंख्यकों को ख़ौफ़ज़दा और नाराज किये है। नाराजगी की वजह पुलिस या प्रशासन की खिलाफत नहीं बल्कि पूरी कार्रवाई में बरती गई गैर वाजिब प्रक्रिया है। वैसे भी सूबे के बस्तर इलाकों में लगातार इसाई मतावलंबियों और चर्चों पर हमले जारी हैं। कट्टरवादी छत्तीसगढ़ की फ़िज़ा में किसके इशारे पर ज़हर घोलने में लगे हैं इसका पता लगाने के बदले पुलिस अल्पसंख्यकों को ही टारगेट में रख रही है। सालों और महीनों पहले रायपुर से हज तथा उमरा के लिए गए लोगों द्वारा एक आईएमओ मोबाइल एप अपलोड करने से पुलिस ने सभी से किसी संदिग्ध गंभीर आरोपी सा दुर्व्यवहार कर सरकार को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। पूरी कार्रवाई ने विपक्षियों को बैठे बिठाये मुद्दा दे दिया है और शासन तंत्र को अल्पसंख्यकों के खिलाफ खड़ा दिखा दिया है।

शहर सत्ता/ शेख आबिद

रायपुर। आधी रात राजधानी रायपुर पुलिस का 150 मुस्लिमों के घरों पर दबिश देने का मामला अब टूल पकड़ता जा रहा है। अघोषित गिरफ्तारियों के खिलाफ मुस्लिम समुदाय के समर्थन में समाज की सभी जमातें भी उठ कड़ी हुई हैं। बता दें कि कुल 115 को पूछताछ के लिए 23 दिसंबर को रायपुर पुलिस ने अघोषित गिरफ्तार किया था। जानकारी के मुताबिक यह कार्रवाई रायपुर पुलिस के अधिकांश बड़े थाना स्तर पर की गई थी। हालांकि पूछताछ के लिए जो प्रक्रिया अपने गई मुस्लिम समाज और पीड़ित पक्ष उसे अपमानजनक मन रहा है। खासकर सिविल लाइन पुलिस ने कुल 12 लोगों को जिन तीन महिलाओं वरिष्ठ अधिवक्ता और 9 पुरुष 4 बुजुर्ग समेत कई युवाओं को भी साढ़े 4 घंटे तक बिना वजह बताये बैठाए रखा था। मामले की जानकारी के बाद पुलिस लाइन में भी नजरबंद रखे गए मुस्लिम लोगों की खबर लेने जमात के सदर और नामचीन लोग गए तो पुलिस के व्यव्हार से सभी आहत हुए।

क्या है आईएमओ मोबाइल एप

विवाद की असल वजह एक कथित आईएमओ विदेशी मोबाइल एप है। इस मोबाईल एप पर भारत में बैन है लेकिन सऊदी अरब में नहीं है। इसके मार्फ़त आसानी से हज के लिए जाने वालों को अपने घर वालों का खैर मकदम लेना सस्ता और आसान है। साथ ही इस एप के जरिये मुस्लिम समुदाय के धार्मिक तीर्थों के साथ रस्मों-रिवाज के बारे में भी जानकारी मिलती है। रायपुर से गए जायरीनों (हज यात्रियों) ने इसे डाऊनलोड किया था। हज कमेटी ने भी या पुलिस और प्रशासन ने भी इस एप के संबंध में इन लोगों को सावचेत नहीं किया था। ऐसे में अनजाने में आईएमओ एप से इण्डिया आने के बाद इक्का-दुक्का बार बात करने की सजा आधी रात और अलसुबह पुलिस की बर्बर कार्रवाई के तौर पर भुगतना पड़ा।

- मुस्लिम युवा से लेकर बुजुर्ग, महिलाओं तक घंटों रहे नजरबंद
- 23 दिसंबर को रायपुर पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ नाराजगी
- रायपुर पुलिस ने किया था 115 ज़ायरिनों को अघोषित गिरफ्तार
- मुस्लिम जमात और क्रिश्चियन फोरम ने की माफ़ी की मांग
- महज आईएमओ मोबाइल एप डाऊनलोड करने पर बरती गई सख़्ती

त्वरित टिप्पणी

प्रदीप चंद्रवंशी

पसंद-नापसंद से इतर सोचो 'जनाब'

आपने देखा होगा कि लोग बड़े गर्व से अक्सर कहते हैं, 'मुझे यह पसंद है, इसलिए मैं यह करके रहूंगा और वह मुझे पसंद नहीं है, इसलिए उसे मैं बिल्कुल नहीं करूंगा, क्योंकि मैं स्वाधीन हूं।' क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि यह सोच सचमुच आपकी स्वाधीनता से जन्मा है? यह स्वाधीनता नहीं है, यह तो बेबसी है, लाचारी है। पसंद और नापसंद की बेड़ियों में आज लगभग पूरी मानवता जकड़ी हुई है। सभी पारिवारिक और सामुदायिक झगड़ों की जड़ में लोगों की व्यक्तिगत पसंद और नापसंद ही होती हैं। पसंद और नापसंद को लेकर समाज, राष्ट्र और धर्म तक बंटे हुए हैं। जब हमारे सोच का दायरा बहुत सीमित होता है, हम कई तरह के पूर्वाग्रहों से ग्रस्त हो जाते हैं, फिर हम पर पसंद और नापसंद की सनक सवार हो जाती है। तब हम उसे नहीं देख पाते, जिसकी जरूरत है। हम वही करते हैं, जिसे हम पसंद करते हैं। वह नहीं करते, जिसे किए जाने की आवश्यकता है। फिर शुरू होता है अविराम झंझटों व विवादों का सिलसिला और उसी में उलझकर रह जाता है हमारा समाज, देश-राज्य और लघु-जीवन।

योग परंपरा में भीतरी आयाम को बहुत गहराई से देखा गया और भीतरी पराधीनता से मुक्त होने की कई तकनीकों का आविष्कार किया गया, क्योंकि जो भीतरी पराधीनता का शिकार नहीं है, उसे कोई बाहरी शक्ति उस पर नियंत्रण नहीं कर सकती। पसंद और नापसंद की सनक से मुक्त होने के लिए हमें अपनी चेतना पर काम करना होगा। एक जागरूक व्यक्ति ही यह देख पाने में सक्षम होता है कि किसी विशेष परिस्थिति में क्या आवश्यक है और क्या किया जाना चाहिए। यह सुझाव शासन, प्रशासन और पुलिस तंत्र के लिए भी है।

कार्रवाई के खिलाफ मुखर हुए अधिवक्ता

सदस्य, छत्तीसगढ़ राज्य विधिक परिषद विराट वर्मा ने पुलिसिया कार्रवाई के खिलाफ पीड़ितों के समर्थन में विज्ञप्ति जारी कर चेतावनी दी है कि अगर 72 घंटे के भीतर वरिष्ठ अधिवक्ता जाकिर अलि से माफ़ी नहीं मांगी गई तो वो मामला कोर्ट तक लेकर जायेंगे। बता दें कि उनके निवास से प्रातः 5 बजे इस प्रकार थाने ले जाना अत्यंत अपमानजनक एवं अनुचित है। उनके साथ की गई यह कार्रवाई न केवल उनके व्यक्तिगत सम्मान के विरुद्ध है, बल्कि समस्त अधिवक्ता समुदाय का भी अपमान है। मोबाइल फोन पर IMO से कॉल आना कोई अपराध नहीं है, विशेषकर जब संबंधित व्यक्ति को इसकी जानकारी ही न हो। यदि पुलिस को किसी प्रकार की जांच करनी थी, तो विधिवत सम्मन/नोटिस जारी कर श्री सैयद जाकिर अली जी को थाने बुलाया जा सकता था। वे एक जिम्मेदार नागरिक एवं अधिवक्ता हैं तथा कानून के पालन के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस प्रकार की अपमानजनक कार्रवाई से न्याय प्रणाली में जनता का विश्वास कमजोर होता है, जो अत्यंत चिंताजनक है।

निम्न बिंदुओं पर अपील

- संबंधित थाना प्रभारी (नाम, यदि ज्ञात हो) के विरुद्ध तत्काल विभागीय जांच प्रारंभ की जाए।
- संबंधित अधिकारी द्वारा 48 घंटे के भीतर वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सैयद जाकिर अली जी से लिखित रूप में माफ़ी मांगी जाए।
- भविष्य में किसी भी अधिवक्ता के विरुद्ध कोई भी कार्रवाई करने से पूर्व विधिवत कानूनी प्रक्रिया का पालन सुनिश्चित किया जाए तथा स्थानीय बार एसोसिएशन/राज्य विधिक परिषद को सूचित किया जाए।
- इस घटना की स्वतंत्र जांच कराई जाए तथा जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए।
- भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने हेतु सभी थानों में स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए जाएं।

1973 से वक़कलत कर रहे हैं। 1996 से 2000 तक छत्तीसगढ़ कॉलेज में प्रोफेसर रहे। 2000 से अब तक सौ.का.कुसुमताई दबके विधि महाविद्यालय में प्राचार्य हैं। 15 से 20 पुलिस वाले घर अल सुबह पकड़कर ले गए। उन्होंने साढ़े 7 से साढ़े 11 बजे तक रखे और मोबाइल में एक एप के सम्बन्ध में पूछताछ किये। लेन की वजह पूर्वी तो उन्होंने बताया IMA मोबाइल एप हज में गया था तब लोड किया था बातचीत के लिए उस सम्बन्ध में पूछताछ किये। एक कजिन ने मक्का में डिनर पर बुलाया था उसकी फोटो थी तो सवाल जवाब किये। क़ानूनी ढंग से उन्होंहे नहीं बुलाया जबरदस्ती 4 घंटे बिठाये रखा। मैं हार्ट पेशेंट हूँ बीपी है सुबह दवा खता हूँ। शासकीय अधिवक्ता रहा हूँ जो पूछताछ किये उन्हें मई नहीं जनता कुछ बुजुर्ग महिलाओं से भी वही तरीका अपनाये सीनियर सिटीजन थे 70 की उम्र के आसपास के लोगों से अपमानजनक पूछताछ किये जो ठीक तरीका नहीं लगा।

वरिष्ठ अधिवक्ता एवं पीड़ित सैय्यद ज़ाकिर अलि बैरन बाजार

इस पुरे मामले में पुलिस कार्रवाई या किसी समुदाय विशेष के मामले हस्तक्षेप नहीं करूँगा। लेकिन मैं सय्यद जाकिर अलि वरिष्ठ अधिवक्ता और लॉ कॉलेज के प्राचार्य और सम्मानित शख्सियत हैं। मैं इस पुरे मामले में एसएसपी से मिला तो उन्होंने माफ़ी मंगवाने की बात कही। अधिवक्ता संघ इस पुरे मामले में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को 72 का समय दिए हैं ताकि उनके द्वारा वरिष्ठ अधिवक्ता से की गई गिरफ़्तारी प्रक्रिया और दुर्व्यवहार के लिए माफ़ी नहीं मंगवाते हैं तो वकील रिट दायर करेंगे और मामले को कोर्ट ले जायेंगे।

अधिवक्ता विराट वर्मा सदस्य, छत्तीसगढ़ राज्य विधिक परिषद

सुबह सुबह मुझे मुस्लिम समाज के और पीड़ित परिवार वालों के फोन आने शुरू हो गए थे। पूरी जानकारी के बाद समाज चंद वरिष्ठ लोगों के साथ रायपुर पुलिस लाइन में जिन्हें रखा गया था उनसे मिलने गया। कोई अधिकारी मौके पर नहीं मिले और न ही किसी जिम्मेदार अफसर कर्मी ने पुरे 115 लोगों को लेन की पुख्ता वजह बताई। बार बार पूछने पर भी जब मामला किसी को समझ नहीं आया तो आला अफसरों से फोन पर संपर्क करने की कोशिश की गई लेकिन किसी ने फोन नहीं उठाया। मुझे यह खबर छानकर आ रही थी कि बांग्लादेशी, रोहिंग्या और पाकिस्तानी समर्थकों के शक पर सभी को लाया गया है। मुझे तब आश्चर्य हुआ जब गिरफ्तार लोगों में 70 की उम्र के वो शहरी बाशिंदे भी थे जिनके बाप-दादा राजधानी रायपुर में सम्मानित नाम हैं। इनमे से कुछ तो सरकारी ओहदों में भी रहे हैं और वर्तमान में भी हैं। मुझे या सीरत कमिटी को क़ानूनी प्रक्रियाओं से कोई परहेज न ही एतराज है। लेकिन इस पुलिसिया हथकंडे की और अपमानजनक कार्रवाई की मज्ज्मत करता हूँ।

सोहेल सेठी, सदर सीरत कमेटी रायपुर

घुसपैठियों की बढ़ती संख्या से राज्य की सुरक्षा को गंभीर खतरा निर्माण हो गया है, सामाजिक अस्थिरता बढ़ रही है, अपराधों में वृद्धि हो रही है, रोजगार की समस्या उत्पन्न हो रही है, और फर्जी दस्तावेजों पर रहने वाले घुसपैठियों का एक बड़ा रैकेट सक्रिय हो चुका है। इस समस्या के समाधान के लिए मा. उपमुख्यमंत्री श्री. विजय शर्मा जी के नेतृत्व में जो कड़ी करवाई का अभियान चलाया जा रहा है इसके लिए हिन्दू जनजागृति समिति सभी देशप्रेमी नागरिको की ओर से अभिनन्दन करती है। खोज अभियान सम्पूर्ण राज्य में आरंभ कर घुसपैठियों के विरुद्ध कड़ी करवाई की जाए ऐसी मांग हिन्दू जनजागृति समिति पुनः कर रही है | साथ ही इस देशहितैषी कार्य को विरोध करने वाले कांग्रेसी नेता, मुस्लिम नेता, वामपंथी इन लोगो के विरुद्ध देशविरोधी शक्तीयों का समर्थन करना, यह देशद्रोहही है, इस दृष्टीसे कानूनी कारवाई करना आवश्यक है, ऐसी भी मांग हिन्दू जनजागृति समिति के महाराष्ट्र एवं छत्तीसगढ़ राज्य संघटक शासन से करता है |

सुनील घनवट, महाराष्ट्र एवं छत्तीसगढ़ राज्य संगठक हिंदू जनजागृति समिति

पुलिस प्रशासन पुरे मुस्लिम समाज और पीड़ित पक्षों से माफ़ी मांगे। इनके द्वारा की गई वर्ग विशेष के खिलाफ कार्रवाई टारगेट कर की गई है। इससे हमारे मान सम्मान और समाज के सम्मानित बुजुर्गों से किया गया दुर्व्यवहार पुलिस चंद कट्टरवादी सोच वाले नेताओं के सामने अपना नंबर बढ़ने के लिए मुस्लिम समाज को प्रताड़ित कर रहा है। इसे तत्काल रोका जाये और भविष्य में ऐसी गैर क़ानूनी प्रक्रिया करने पर पूरा समाज उठ खड़ा होगा और सख्त विरोध करेगा।

राहिल रउफी, हुसैनी सेना मुस्लिम समाज

23 दिसंबर को पुलिस का समाज के 115 परिवारों को आधी रात से अल-सुबह तक यूं परेशान करना वह भी एक मोबाइल एप डाऊनलोड करने की वजह से सहीं नहीं लगा। जबकि मेरी जानकारी में इस एप के संबंध में लोगों की बुरी नियत से अपलोड नहीं करने की जानकारी है। अगर ऐसा कोई एप है जिस पर पाबन्दी है तो पुलिस और प्रशासन के साथ साथ हज कमेटी या अलप संख्यक आयोग के मार्फ़त समुदाय विशेष को ख़बरदार करना चाहिए। ताकि ऐसी नौबत भी नहीं आए और मुस्लिम समुदाय भी ऐसी अपमानजनक कार्रवाई से अछूता रहे। शहरी नामचीन लोगों और सम्मानित बुजुर्गों को हज और उमरा के दौरान घर पर बात करने के लिए इस एप को मियादी तारीख तक उपयोग करने की छूट है।

नुमान अकरम , पूर्व सदर सीरत कमेटी रायपुर

रायपुर के सम्मानित लोगों को लौटने के बाद जिस तरह रायपुर पुलिस ने उनके खिलाफ एक्शन लिया है वो गलत है। हज यात्रियों को जो पीड़ित किया गया अघोषित गिरफ़्तारी की गई वह गैर संवैधानिक है और इसकी छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फोरम निंदा करता हैं। इसाई समाज भी यही सब कुछ झेल रहा है इसलिए हम मुस्लिम समाज के साथ है। कांकेर में भी इसाई परिवार और चर्च में किये गए हमले से प्रदेश की किरकिरी हो रही है। अचानक ही छत्तीसगढ़ में इसाईयों और चर्चों में कथित आरोप लगाकर हमले हो रहे हैं।

अंकुश बरियेकर, महासचिव छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फोरम

रायपुर पुलिस की 23 दिसंबर 2025 को की गई मुस्लिम समाज के लोगों के खिलाफ कार्रवाई विधि सम्मत नहीं थी। महज एक एप के नाम पर समः के नामचीन, बुजुर्गों और महिलाओं को कड़कड़ाती ठंड में जिस तरह घर में दबिश देकर बयान के नाम पर बुलाकर ले जाना कानूनन सही नहीं कहा जा सकता। खासकर बुजुर्ग और वरिष्ठ अधिवक्ता जाकिर जी को साढ़े 4 घंटे तक बयान के नाम पर बैठाना अपमानजनक है। पुलिस कार्रवाई के ये शिकार सभी लोग कोई संदिग्ध लोहिंग्या, बांग्लादेशी या पाकिस्तानी नहीं बल्कि हज के लिए गए जायरीन थे। इस पूरी कार्रवाई को लेकर मुस्लिम समुदाय खुद को अपमानित महसूस कर रहा है रायपुर पुलिस और इस तरह की कार्रवाई का आदेश देने वालों को समाज से माफ़ी मांगना चाहिए। प्रशासन को यह भी तय कर लेना चाहिए कि आइंदा ऐसे पुनरावृत्ति नहीं हो।

फैज़ल रिज़वी, वरिष्ठ अधिवक्ता हाई कोर्ट बिलासपुर

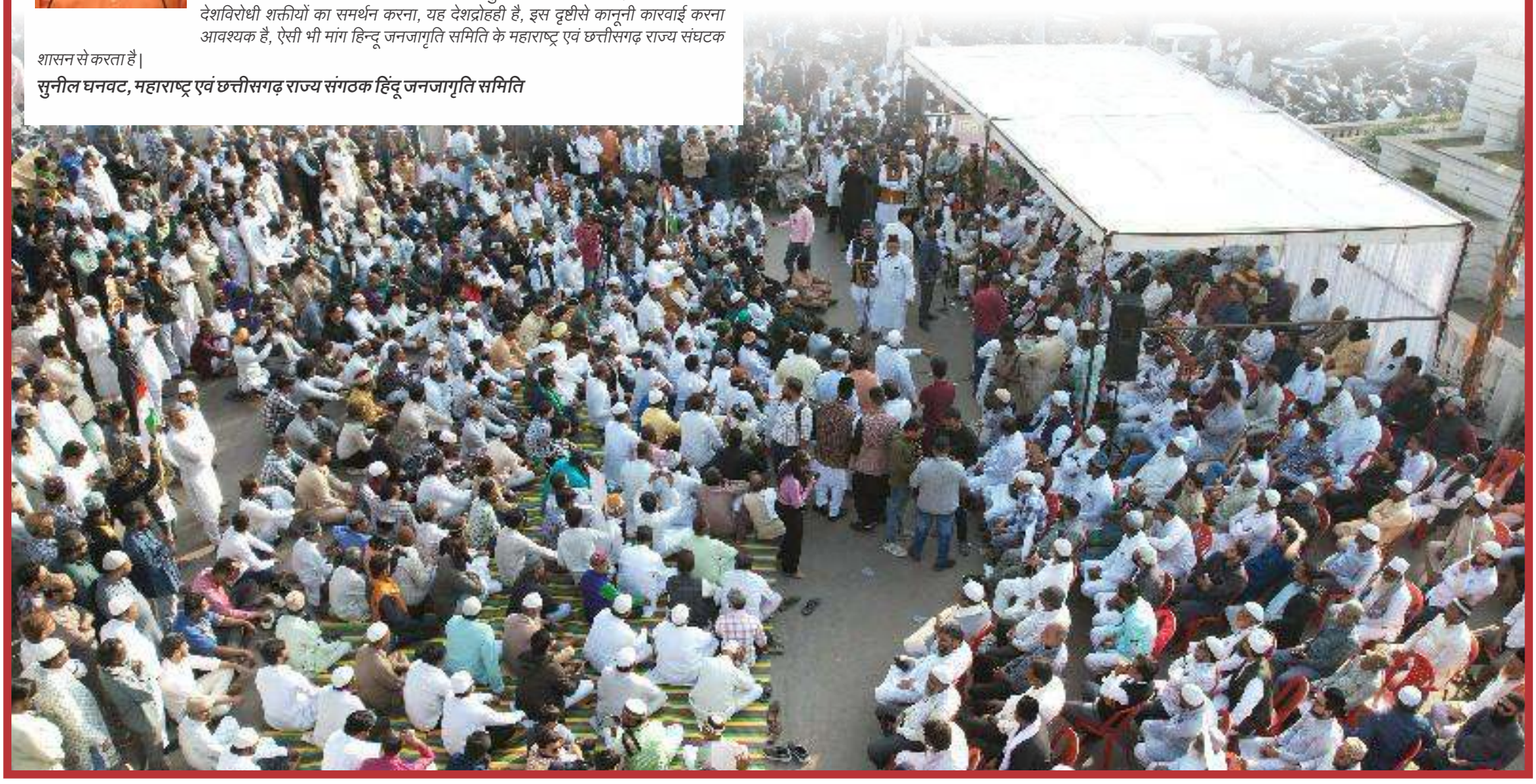

भाजयुमो ने जलाया पूर्व सीएम भूपेश बघेल का पुतला

कथावाचक धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री पर की गई टिप्पणी के खिलाफ जंगी प्रदर्शन

शहर सत्ता/रायपुर। सनातन धर्म को लेकर जारी सियासी बयानबाजी के बीच भारतीय जनता युवा मोर्चा (भाजयुमो) ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ प्रदेशभर में प्रदर्शन किया। भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने उन्हें "सनातन विरोधी" बताते हुए कई जिलों में पुतला दहन किया और कांग्रेस पर भगवान श्रीराम तथा साधु-संतों के अपमान का आरोप लगाया।

रायपुर में हुए प्रदर्शन के दौरान भाजपा रायपुर शहर जिला अध्यक्ष रमेश सिंह ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने लगातार सनातन धर्म का विरोध किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि भूपेश बघेल अंतरराष्ट्रीय कथा वाचक पं. प्रदीप मिश्रा और पं. धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का विरोध कर रहे हैं, जिससे यह साफ होता है कि कांग्रेस नेताओं को किसी तय स्क्रिप्ट के तहत सनातन पर हमला करने के निर्देश दिए जाते हैं।

रमेश सिंह ठाकुर ने कहा कि जब रामसेतु का मुद्दा उठा था, तब कांग्रेस नेताओं ने उसे काल्पनिक बताया और भगवान श्रीराम के अस्तित्व पर सवाल खड़े किए। उन्होंने यह भी कहा कि राम मंदिर निर्माण के बाद आमंत्रण मिलने के बावजूद गांधी परिवार दर्शन के लिए नहीं गया, जो कांग्रेस की मानसिकता को दर्शाता है। "हमारे आस्था केंद्रों का अपमान बर्दाश्त नहीं"भाजयुमो ने कहा कि कांग्रेस नेताओं ने लगातार सनातन धर्म, साधु-संतों और भारतीय परंपराओं का अपमान किया है। उन्होंने कहा कि पंडित प्रदीप मिश्रा के प्रवचनों और शिव भक्ति से गांव-गांव में सनातन चेतना जागृत हो रही है, वहीं धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री सनातन संस्कृति को मजबूती देने का काम कर रहे हैं। भाजयुमो ने आरोप लगाया कि जो लोग दिल्ली में धर्मांतरण कराने वालों को संरक्षण देते हैं, उन्हें सनातन धर्म और साधु-संतों पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने दावा किया कि सनातन विरोध की राजनीति करने वाली कांग्रेस अब कुछ राज्यों तक सिमट कर रह गई है और आने वाले समय में उसका जनाधार और कमजोर होगा।

इस दौरान भाजयुमो के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे, जिनमें अमन प्रताप, विशाल पांडेय, वासु शर्मा, पिंटू साहू, अर्पित सूर्यवंशी, प्रणय साहू, अश्वनी विश्वकर्मा, शंकर साहू, अभिषेक धनगर, योगी साहू, शुभांकर द्विवेदी, युगल वर्मा, भारत कुंड, आकाश शर्मा, राहुल वर्मा सहित अन्य शामिल थे।

भूपेश बोले- धीरेंद्र शास्त्री भाजपा के एजेंट

CM ने कहा-ये सनातन का अपमान; छिड़ा विवाद

शहर सत्ता/रायपुर। छत्तीसगढ़ के भिलाई में चल रही पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की कथा के दौरान उठे विवाद ने राजनीतिक रूप ले लिया है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कथावाचक पं. धीरेंद्र शास्त्री के 'देश छोड़ दें' वाले बयान पर पलटवार किया। उन्होंने धीरेंद्र शास्त्री को बीजेपी का एजेंट बताया। वहीं भूपेश बघेल के बयान पर CM विष्णुदेव साय ने कहा कि भारत ऋषि मुनियों का देश रहा है। हमेशा से ऋषि मुनियों का सम्मान होता आया है। अगर भूपेश बघेल पं. धीरेंद्र शास्त्री को बीजेपी का एजेंट कह रहे हैं तो यह सनातन का अपमान है। बागेश्वर धाम का अपमान है। जनता इस पर निर्णय लेगी।

बाबा बोले-जिस पत्रकार को खुजली हो,वो सवाल पूछे

इसके अलावा बागेश्वर बाबा का एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में धीरेंद्र शास्त्री पत्रकारों पर विवादित बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। धीरेंद्र शास्त्री कहते हैं कि जिस पत्रकार को खुजली हो, वो सवाल पूछ सकता है। इसे कांग्रेस ने पत्रकारों का अपमान बताया है। वहीं वरिष्ठ पत्रकार सुनील कुमार ने कहा कि आज पत्रकारों को वहां बैठे रहना। आशीर्वाद लेना उनको सुहा रहा है, तो वो ऐसी भाषा के ही हकदार हैं।

सत्ता के संरक्षण में पल रहा घमंडः कांग्रेस

पत्रकारों पर अभद्र टिप्पणी के मामले में कांग्रेस ने एक्स पर लिखा कि पत्रकार खुद से नहीं गए थे बल्कि भाजपा नेताओं ने उन्हें बुलाया था, फिर ऐसा अपमान क्यों ? यह सिर्फ बदतमीजी नहीं, बल्कि सत्ता के संरक्षण में पल रहा घमंड है। कांग्रेस ने आगे लिखा जब पूरी सरकार ही चरण वंदना में लगी हो, तो इनकी जबान का बेलगाम होना स्वाभाविक है।

राजीव भवन में कांग्रेस का 141वां स्थापना दिवस

स्वतंत्रता आंदोलन में कांग्रेस थी जनमानस की आवाज

शहर सत्ता/रायपुर। कांग्रेस का 141वां स्थापना दिवस रविवार को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज द्वारा पार्टी ध्वज फहराने से हुई। सेवादल के जवानों ने सलामी दी। इसके बाद आजादी की लड़ाई से लेकर देश के नवनिर्माण तक कांग्रेस की भूमिका पर संगोष्ठी आयोजित की गई। संगोष्ठी में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, वरिष्ठ नेता सत्यनारायण शर्मा और राजेंद्र तिवारी ने कांग्रेस के ऐतिहासिक योगदान पर अपने विचार रखे। स्वागत भाषण शहर जिला अध्यक्ष श्रीकुमार मेनन ने दिया, जबकि आभार ग्रामीण जिला अध्यक्ष राजेंद्र पप्पू बंजारे ने जताया। संचालन महामंत्री सुबोध हरितवाल ने किया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि कांग्रेस ने 140 साल का सफर पूरा कर लिया है और आज भी देश का इकलौता ऐसा राजनीतिक दल है, जिसका कार्यकर्ता उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक हर गांव में मिलेगा।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हर दौर की जरूरत के अनुसार अपनी प्राथमिकताएं तय कीं। आजादी से पहले स्वतंत्रता आंदोलन और आजादी के बाद संविधान निर्माण, गणतंत्र की स्थापना और राष्ट्र निर्माण कांग्रेस की बड़ी उपलब्धियां हैं। दीपक बैज ने कहा कि नेहरू युग में पंचशील और गुटनिरपेक्षता की नीति बनी, शास्त्री जी के समय 'जय जवान, जय किसान' का नारा दिया गया। इंदिरा गांधी के दौर में हरित क्रांति, अंतरिक्ष और परमाणु कार्यक्रम आगे बढ़े। राजीव गांधी ने देश को आईटी और कंप्यूटर क्रांति से जोड़ा और युवाओं को लोकतंत्र से जोड़ा। मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी के नेतृत्व में मनरेगा, खाद्य सुरक्षा, शिक्षा का अधिकार और सूचना का अधिकार जैसे कानून बने, जिसने आम आदमी का जीवन बदला।

ड्रोन से पकड़ा गया जुएं का फड़, 31 लाख रुपये की संपत्ति जब्त

शहर सत्ता/रायपुर। शहर में अवैध जुआ और पार्टी संस्कृति पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए रायपुर पुलिस द्वारा लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट तथा थाना मुजगहन पुलिस की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक फार्म हाउस में जुआ खेलते हुए 16 जुआरियों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से नकदी, वाहन, मोबाइल फोन और ताशपत्ती सहित लगभग 31 लाख रुपये की संपत्ति जब्त की है।

जानकारी के अनुसार एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट को सूचना मिली कि थाना मुजगहन क्षेत्रांतर्गत स्थित "हंसी खुशी फार्म हाउस" में अवैध गतिविधियों के साथ ताशपत्ती से जुआ खेला जा रहा है। सूचना की पुष्टि के लिए पुलिस टीम द्वारा ड्रोन कैमरे का इस्तेमाल किया गया, जिसमें स्पष्ट रूप से देखा गया कि फार्म हाउस के भीतर कुछ लोग रुपये-पैसे की हार-जीत का दांव लगाकर जुआ खेल रहे हैं। इसके बाद वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट और थाना मुजगहन पुलिस की संयुक्त टीम ने मौके पर दबिश दी। रेड कार्रवाई के दौरान पुलिस ने जुआ खेलते हुए कुल 16 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से ₹2,12,600 नगद, 02 चारपहिया वाहन, 08 दोपहिया वाहन, 17 मोबाइल फोन एवं ताशपत्ती जब्त की गई। जब्त मशरूका की कुल अनुमानित कीमत लगभग ₹31 लाख बताई गई है।

साप्ताहिक शहर सत्ता

साय के सुशासन में अब नहीं दबेंगी जनहित की फाइलें

सरकारी कामकाज का तरीका पूरी तरह बदल जाएगा

- **जनवरी से बदलेगा सरकारी दफ्तरों में कामकाज का तरीका मंत्रालय, एचओडी और जिलों में होगा ई-ऑफिस**

रायपुर। छत्तीसगढ़ में सरकारी कामकाज में 1 जनवरी 2026 से बड़ा बदलाव आने वाला है। 1 जनवरी, 2026 से समस्त विभागाध्यक्ष, संभाग आयुक्त और कलेक्टर कार्यालय मे संपूर्ण कार्यालयीन नस्ती और डाक का संपादन ई-ऑफिस के माध्यम से ही किया जाएगा। विभाग प्रमुख के अनुमोदन के बिना कोई भी फिजिकल फाइल संचालित नहीं की जाएगी। ऐसे प्रकरण जिस पर शासन स्तर पर सहमति या अनुमोदन की आवश्यकता हो उसे अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा ई-ऑफिस के फाइल के माध्यम से ही शासन को प्रेषित किया जाए। सूचनात्मक पत्राचार ई-ऑफिस के रिसीट (पावती) के माध्यम से किये जाए।

कामकाज के तरीकों में बड़ा बदलाव

जानकारों का मानना है कि राज्य में ई आफिस सिस्टम लागू होने के बाद सरकारी कामकाज के तरीकों में बड़ा बदलाव संभावित है। अभी जो सरकारी दस्तावेज, फाइले मैन्युअल तरीके से चलती है, वह सब कुछ आनलाइन माध्यम से ई आफिस सिस्टम से चलेंगी। इस बदलाव से सरकारी कामकाज में पारदर्शिता आने के साथ ही तेजी भी आएगी। यही नहीं सरकारी लोग जो लोगों के आवेदन, मांग पत्र वगैरह को फाइलों में लपेटकर ठंडे बस्ते में डालने का काम करते रहे है, यह पूरी प्रक्रिया ही बदल जाएगा। इसके साथ ही सरकारी अधिकारी कर्मचारियों में जवाबदेही भी सुनिश्चित होगी।

होगा ये फायदा

ई-ऑफिस सिस्टम लागू होने से सरकारी कामकाज में काफी सुधार आने की संभावना है। डिजिटल ट्रैकिंग के कारण, यह पता लगाना आसान होता है कि फाइल किस अधिकारी के पास कितने समय से लंबित है, जिससे कार्य में पारदर्शिता आती है और जवाबदेही तय होती है। नस्ती को एक टेबल से दूसरे टेबल पर ले जाने में लगने वाला समय समाप्त हो जाता है। डिजिटल हस्ताक्षर के प्रयोग से फाइलों पर त्वरित निर्णय लिए जा सकते हैं। सुरक्षित अभिलेख संधारणः महत्वपूर्ण शासकीय दस्तावेजों का डिजिटल रूप से सुरक्षित भंडारण सुनिश्चित होता है, जिससे उनके नष्ट होने का खतरा कम हो जाता है। कागज. प्रिंटिंग और फाइल रखने की लागत में भारी कमी आती है, जिससे पर्यावरण संरक्षण में भी मदद मिलती है।

सालभर की कोशिश अब रंग लाएगी

राज्य के मुख्य सचिव ने इस संबंध में प्रदेश के शासन के समस्त विभाग, अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, बिलासपुर, समस्त विभागाध्यक्ष, समस्त संभागायुक्त, समस्त कलेक्टर छत्तीसगढ़ के लिए आदेश जारी कर दिया है। राज्य में पिछले करीब एक साल से ई-आफिस प्रक्रिया शुरु करने की कोशिश की जा रही थी। यह कोशिश जनवरी से रंग लाएगी।

इसलिए लागू हो रही है ये व्यवस्था

मुख्य सचिव ने इस संबंध में जारी आदेश में साफ किया है कि यह व्यवस्था क्यों लागू की जा रही है। उनका कहना है कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा सुशासन की दिशा में कार्य करते हुए प्रदेश में शासकीय कार्य को अधिक प्रभावी, सरलीकृत, उत्तरदायी, और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से मंत्रालय, विभागाध्यक्ष और जिले स्तर पर ई-ऑफिस प्रारम्भ किया गया है। मंत्रालय के समस्त विभागों और राज्य के विभिन्न कार्यालयों में ई-ऑफिस के माध्यम से नस्ती और डाक का संपादन किया जा रहा है।

ई आफिस सिस्टम से चलेंगी फाइलें

ऐसे प्रकरण जिस पर शासन स्तर पर सहमति या अनुमोदन की आवश्यकता हो उसे अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा ई-ऑफिस के फाइल के माध्यम से ही शासन को प्रेषित किया जाए। सूचनात्मक पत्राचार ई-ऑफिस के रिसीट (पावती) के माध्यम से किये जाए। अफसर बाहर से और छुट्टी के दिन भी काम कर सकते हैंराज्य में यह सिस्टम लागू होने यह सुविधा भी मिलेगी कि अधिकारियों द्वारा शासकीय प्रयास के दौरान मुख्यालय से अन्यत्र भी ई-ऑफिस के माध्यम से कार्य संपादित कर सकेंगे।) सार्वजनिक अवकाश अवधि में शासकीय सेवक ईऑफिस के माध्यम से जरूरत के हिसाब से काम कर सकते हैं।

कुशाभाऊ ठाकरे को दी गई श्रद्धांजलि

रायपुर। अद्भुत संगठन शिल्पी, त्याग और सादगी की प्रतिमूर्ति और विश्वविद्यालय के प्रेरणास्त्रोत श्रद्धेय कुशाभाऊ ठाकरे जी की 22वीं पुण्यतिथि में उनकी प्रतिमा स्थल पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय, रायपुर के कुलपति एवं संभागायुक्त महादेव कावरे ने पुष्पाजंलि अर्पित करने के उपरांत अपने संक्षिप्त वक्तव्य में कहा कि श्रद्धेय कुशाभाऊ ठाकरे जी सादगी, शुचिता और सिद्धांतों के प्रकाश स्तंभ रहे हैं। राष्ट्र निर्माण और संगठन को मजबूत करने में आपका अतुलनीय योगदान अविस्मरणीय है। सामाजिक-राजनीतिक जीवन में शीर्ष नेतृत्वकर्ता होने के साथ ही हजारों कार्यकर्ताओं के मार्गदर्शक और आदर्श रहे। उनके राष्ट्र सेवा का भाव हमें निरंतर कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ने की शक्ति प्रदान करता है। ठाकरे जी महान राष्ट्रवादी चिंतक हैं, आपके आदर्श जीवन और मूल्यों से प्रेरित छत्तीसगढ़ शासन द्वारा स्थापित पत्रकारिता विश्वविद्यालय अपने विद्यार्थियों के लिए सदैव प्रेरणा का केंद्र रहेंगा।

कुशाभाऊ ठाकरे जी के ग्राम स्वालंबन के विचारों से प्रेरित होकर एवं छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के सतत् मार्गदर्शन में ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कई कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इसी कड़ी में विश्वविद्यालय के गोद ग्रामों की महिलाओं को पैरा एवं फूलों के आर्ट क्रॉफ्ट का विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य आजीविका मिशन बिहान के धरसींवां विकासखंड और सहेली सोशल वेलफेयर फाउंडेशन, नवागांव के सहयोग से 10 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन जनसंचार विभाग सभागृह में किया गया है। सभा में कार्य परिषद सदस्य प्रभात मिश्र और कुलसचिव सुनील कुमार शर्मा ने भी श्रद्धांजलि वक्तव्य दिया। सभा का संचालन शैलेन्द्र खंडेलवाल ने और आभार प्रदर्शन सौरभ शर्मा उपकुलसचिव ने दिया। इस अवसर पर प्राध्यापक गण डॉ. नृपेन्द्र कुमार शर्मा, डॉ. राजेन्द्र मोहंती सहित अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

रायपुर सहित प्रमुख शहरों में रेल संचालन क्षमता होगी दोगुनी

कनेक्टिविटी और आर्थिक गतिविधियां होंगी सुदृढ़

- **साय ने पीएम-रेलमंत्री का जताया आभार**

रायपुर। भारतीय रेलवे द्वारा अगले पांच वर्षों में देश के 48 प्रमुख शहरों में रेलगाड़ियों की संचालन क्षमता को दोगुना करने की जो महत्वाकांक्षी योजना तैयार की गई है, उसमें छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर को भी शामिल किया गया है। इस निर्णय का स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि यह छत्तीसगढ़ के करोड़ों यात्रियों के लिए बड़ा तोहफ़ा है। इससे राज्य की कनेक्टिविटी, व्यापार, उद्योग तथा पर्यटन गतिविधियों को नया आयाम मिलेगा।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय रेलवे का व्यापक आधुनिकीकरण हो रहा है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा घोषित इस योजना से छत्तीसगढ़ जैसे उभरते हुए राज्य को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि रायपुर जंक्शन देश के प्रमुख रेल जंक्शनों में से एक है। यहां प्रतिदिन लाखों यात्री आवागमन करते हैं। संचालन क्षमता दोगुनी होने से लोगों को अधिक ट्रेनें, बेहतर आवृत्ति तथा कम भीड़भाड़ का लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि रायपुर के साथ-साथ अन्य औद्योगिक और वाणिज्यिक नगरों के लिए भी यह योजना अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगी। रेल संरचना के विस्तार से निवेश, रोजगार और लॉजिस्टिक्स की सुगमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। इससे राज्य की अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार मिलेगी।

धीरेंद्र शास्त्री के पैर छूने वाले टीआई के लाइन अटैच की चर्चा अफसरों ने कहा- कार्रवाई नहीं

रायपुर। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर, कथावाचक धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के ऑन ड्यूटी टीआई द्वारा पैर छूने का मामला जमकर वायरल हो रहा है। इसी बीच

टीआई के लाइन अटैच होने की चर्चा दिनभर होती रही। टीआई के लाइन अटैच होने की पुष्टि करने हरिभूमि की टीम ने पुलिस अफसरों से किया, तो अफसरों ने टीआई के किसी तरह के लाइन अटैच या किसी तरह की कार्रवाई से इनकार संपर्क किया है। दुर्ग के एक कार्यक्रम में शामिल होने रायपुर पहुंचे। इस दौरान स्टेट हैंगर में कथावाचक की सुरक्षा में लगे माना टीआई मनीष तिवारी ने कथावाचक को सैल्यूट करने के बाद उनका पैर छूकर आशीर्वाद लिया। पैर छूने का वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल होने लगा। वीडियो वायरल होने पर कई लोगों ने पुलिस प्रोटोकॉल के विपरीत बताया है, तो एक वर्ग के लोगों ने इसे आस्था से जोड़ते हुए धीरेंद्र शास्त्री के पैर छूने की घटना को सामान्य बताया है। टीआई द्वारा धीरेंद्र शास्त्री के पैर छूने की घटना को राजनीतिक पार्टी से जुड़े लोग राजनीतिक रंग देने लगे हैं।

दुर्गा नगर झुग्गी बस्ती को बचाने एकजुट हुआ गाड़ा समाज

रायपुर। सामाजिक युवा नेता भरत छुरा, हेमलाल नायक, चंदू बघेल, गुड्डु भतरिया ने संयुक्त विज्ञप्ति जारी कर बताया राजधानी रायपुर के हृदय स्थल में स्थित दुर्गा नगर झुग्गी बस्ती के 120 परिवारों के भविष्य पर एक बार फिर से संकट के बादल मंडरा रहे हैं। नगर निगम द्वारा एक 1600 करोड़ के प्रोजेक्ट के नाम पर इन गरीब परिवारों को शहर से लगभग 15 किलोमीटर दूर, बुनियादी सुविधाओं से वंचित पुराना विधानसभा के आगे 'पिरदा' इलाके में विस्थापित करने की तैयारी के विरोध में बस्ती के निवासी और पूरा गांड़ा समाज एकजुट होकर खड़ा हो गया है।

आज, दुर्गा नगर में आयोजित एक ऐतिहासिक महाबैठक में सैकड़ों की संख्या में सामाजिक मुखिया, नेता, पदाधिकारी, कार्यकर्ता और समाजजन उपस्थित हुए। सभी ने एक स्वर में यह घोषणा की कि दुर्गा नगर को बचाना है और किसी भी हाल में अन्यायपूर्ण विस्थापन को स्वीकार नहीं किया जाएगा। आज की महाबैठक में विभिन्न राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों के नेताओं ने दुर्गा नगर के निवासियों के साथ एकजुटता व्यक्त करते हुए सरकार की इस नीति पर आपत्ति जतायी है। किशोर महानंद (भाजपा के पूर्व प्रदेश मंत्री) ने कहा "हम अपने लोगों के आशियाने को उजड़ने नहीं देंगे। जो जहां है, उसे वहीं मकान बनाकर दिया जाए। समाज इस मामले में एक साथ खड़ा है।" अधिवक्ता भगवानू नायक (जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के मुख्य प्रवक्ता ने कहा "यह गरीब और दलित विरोधी नीति है। जिस जगह में जिनकी कई पीढ़ियां गुजर गईं, उन्हें वहीं रहने दिया जाए। उनको हटाना असंवैधानिक और अव्यावहारिक है। इससे उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार बुरी तरह प्रभावित होंगे।" बनमाली छुरा (सामाजिक नेता ने कहा "शहर से दूर ऐसी जगह, जहां न बिजली है, न पानी है और न ही रोजगार के साधन, वहां हमारे गरीब लोगों को भेजना उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ है।" बसंत बाग (भाजपा अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष ने कहा "सरकार को अपनी नीति पर पुनर्विचार करना चाहिए। गरीबों के साथ किसी भी तरह का अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।"

संपादकीय

सुकांत राजपूत

कथावाचक के बिगड़े बोल

बड़बोले कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री को लेने के लिए सरकारी चार्टर्ड प्लेन का दुरुपयोग कर के सतना लेने गए थे, वही आज छत्तीसगढ़ के सम्मानित पत्रकारों का अपमान कर रहा है। पत्रकारों से कहा जा रहा है कि — "जिस पत्रकार को खुजली हो वह प्रश्न कर सकता है।" सरकार ने धीरेन्द्र शास्त्री को किस संवैधानिक अधिकारों के कारण उनको लेने के लिए विमान भेजा था? एक अवसर दें तो हम खुजली वाले पत्रकारों की एक प्रेस वार्ता का सामना कर लें ऐसे कइयों के मुंह का बवासीर ठीक हो जायेगा। कर्ण पिशाचनी के उपासकों को शायद यह भान नहीं कि कुछ पाने के चक्कर में बहुत कुछ देना भी पड़ता है।

धीरेन्द्र हिन्दू समाज और सनातन के धर्मगुरु नहीं है। वे कथावाचक हो सकते है। तंत्र-मंत्र करने वाले बाबा हो सकते है, वे कोई धर्माचार्य नहीं है, न ही किसी शास्त्र के मान्यता प्राप्त पीठ के पीठाधीश्वर है। उन्हें ज्ञान होना चाहिए कि हिन्दू धर्म, सनातन धर्म जोड़ने का काम करता है। धीरेन्द्र शास्त्री तो मन-मस्तिष्क में परस्पर गरल पान करवा रहे हैं। कभी भरे मंच से हिंदुओं जाग जाओ हाथों में हथियार उठा लो, गैर हिंदुओं के घरों में बुलडोज़र चला दो...जैसे भड़काऊ बयान कच्चे उम्र की अल्पग्यता का ही परिणाम है।

पवनपुत्र प्रेम, सहिष्णुता, वीरता और क्षमा के प्रतिरूप है। हनुमान जी के नाम पर कथा कहकर अपनी गद्दी गर्म करने आजीविका चलाने वाले धीरेन्द्र शास्त्री हनुमान जी के चरित्र से ही सहिष्णुता नहीं सीख पाये हैं। ऐसे में कथा श्रवण करने वालों को वो क्या हनुमान जी के चरित्र की व्याख्या कर पाएंगे? हनुमान जी ने कालनेमि जैसे दुष्ट पाखंड का नाश किया था। जब पूरी सरकार ही चरणवंदना में लगी हो, तो इनकी ज़बान का बेलगाम होना स्वाभाविक है। पत्रकार खुद से नहीं गए थे बल्कि भाजपा नेताओं ने उन्हें बुलाया था, फिर ऐसा अपमान क्यों ? यह सिर्फ बदतमीज़ी नहीं, बल्कि सत्ता के संरक्षण में पल रहा घमंड है।

संतों और पत्रकारों को नववर्ष से यह प्रण कर लेना होगा कि उनके द्वारा जो लिखा जाए, जो पढ़ा जाए, जो बोला जाए वह समाज को जोड़ने वाला हो, वास्तविक हो, उसमें सबकी कहानी हो और जो कुछ अपना-सा महसूस कराए। क्यों न हमारे वर्ड ऑफ द ईयर आने वाले साल में शांति, सद्भाव, समानता और शुभकामना का पर्याय बनाएं।

वीबी-जी राम जी संरचनात्मक कमियों को दूर करता है

शिवराज सिंह चौहान

भारत के राष्ट्रपति ने विकसित भारत- रोज़गार और आजीविका के लिये गारंटी मिशन (ग्रामीण) अधिनियम, 2025 को मंजूरी दी है। यह कानून वैधानिक मजदूरी रोजगार गारंटी को बढ़ाकर 125 दिन करता है और सशक्तिकरण, विभिन्न योजनाओं के आपसी समन्वय और व्यापक वितरण के माध्यम से ग्रामीण आजीविका को मजबूत करता है, ताकि ग्रामीण भारत मजबूत, सक्षम और आत्मनिर्भर बन सके।

सुधारों की गलत व्याख्या

वीबी- जी राम जी अधिनियम लागू होते ही कुछ लोगों ने ऐसी बातें कही हैं, जो गहराई से देखने पर सही नहीं ठहरतीं। कहा जा रहा है कि रोजगार गारंटी कमजोर कर दी गई है, विकेंद्रीकरण और मांग-आधारित अधिकारों को बिना परामर्श के कमज़ोर किया गया है और यह सुधार असल में राजकोषीय खर्च घटाने का तरीका है, जिसे ढांचे में बदलाव के रूप में पेश किया जा रहा है। लेकिन ये सभी दावे इस कानून के असली उद्देश्य और प्रावधानों को ठीक से न समझ पाने के कारण किए जा रहे हैं।

इस गलतफहमी का मूल कारण एक गहरी वैचारिक त्रुटि है- यह मान लेना कि कल्याण और विकास एक दूसरे के विरोधी विरोधी विकल्प हैं। नया ढांचा इसके बिल्कुल उलट सोच पर आधारित है : कल्याण, जो कि वैधानिक आजीविका गारंटी को मजबूत करने पर केंद्रित है, और विकास, जो कि टिकाऊ बुनियादी ढांचे के निर्माण और उत्पादकता वृद्धि पर केंद्रित है, परस्पर एक दूसरे को मजबूत करते हैं। आय सहायता, संपत्ति सृजन, कृषि स्थिरता और लंबे समय की ग्रामीण उत्पादकता को अलग-अलग नहीं, बल्कि एक साथ चलने वाली प्रक्रिया माना गया है। यह केवल कोरी कल्पना नहीं है, बल्कि कानूनी संरचना में ही शामिल सोच है। यह कहना कि कानूनी रोजगार अधिकार कमजोर कर दिया गया है, सही नहीं है। इस कानून में रोजगार गारंटी का वैधानिक और न्यायिक अधिकार बरकरार रखते हुए उसे और मजबूत किया गया है। अधिकार घटाने के बजाय इसे 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया है। पहले जो प्रक्रियागत शर्तें बेरोजगारी भत्ता मिलने में रुकावट बन जाती थीं, उन्हें हटा दिया गया है और समयबद्ध शिकायत निवारण व्यवस्था को और सुदृढ़ किया गया है। यह सुधार लंबे समय से मौजूद उस अंतर को दूर करने का प्रयास है, जो काग़ज़ पर किए गए वादे और लोगों के धरातल के अनुभव के बीच था। यह भी कहा जा रहा है कि मांग-आधारित रोजगार छोड़कर ऊपर से थोपे गए योजनागत मॉडल को लागू कर दिया गया है। यह भी एक गलत धारणा है। काम की मांग पहले की तरह ग्रामीण मजदूरों से ही आती है। फर्क यह है कि अब काम तभी शुरू नहीं किया जाएगा जब मजबूरी या संकट बढ़ जाए, बल्कि पहले से ही भागीदारी आधारित ग्राम-स्तरीय योजना बनाकर तैयारी कर ली जाएगी। इससे यह सुनिश्चित होगा कि जब मजदूर काम मांगें, तो उनके लिए तुरंत काम उपलब्ध हो, और प्रशासनिक तैयारी न होने के कारण उन्हें मना न किया जाए। इस तरह योजना बनाना मांग को दबाता नहीं, बल्कि उसे सही रूप से लागू करता है।

केंद्रीकरण का आरोप इस कानून की पूरी संरचना को नज़रअंदाज़ करता है। ग्राम पंचायतें पहले की तरह ही योजना बनाने और लागू करने की प्रमुख संस्था बनी रहती हैं और ग्राम सभाओं के पास स्थानीय योजनाओं को मंजूरी देने का अधिकार यथावत है। फर्क सिर्फ इतना है कि अब विकेंद्रीकरण बिना व्यवस्था के या कभी-कभार होने वाली प्रक्रिया नहीं रहेगा, बल्कि एक नियमित, व्यवस्थित और सहभागी प्रणाली के रूप में होगा। विकसित ग्राम पंचायत योजनाओं को ब्लॉक, ज़िला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर जोड़ा जाएगा ताकि विभिन्न क्षेत्रों में बेहतर तालमेल, समन्वय और पारदर्शिता हो सके — न कि स्थानीय प्राथमिकताओं को दबाने के लिए। केंद्रित किया गया है सिर्फ व्यवस्था और सामंजस्य को, निर्णय लेने का अधिकार स्थानीय ही रहेगा। इस तरह यह कानून बिखराव को ठीक करता है, विकेंद्रीकरण को कमज़ोर नहीं करता। यह आरोप भी सही नहीं है कि इस सुधार को बिना किसी परामर्श के लागू कर दिया गया। इस विधेयक से पहले राज्य सरकारों के साथ व्यापक विचार-विमर्श, तकनीकी कार्यशालाएँ और विभिन्न हितधारकों के साथ विस्तृत चर्चाएँ की गईं। गांव-स्तरीय योजना संरचना, विभिन्न योजनाओं के बीच समन्वय की व्यवस्था और डिजिटल गवर्नेंस सिस्टम जैसे प्रमुख प्रावधान राज्यों से मिले सुझावों और वर्षों के अनुभव से सीखे गए सबक के आधार पर तैयार किए गए हैं।

आवंटन में वृद्धि, समानता

यह धारणा भी तथ्यों से मेल नहीं खाती कि पिछले दशक में रोजगार गारंटी को लगातार कमजोर किया गया। बजट आवंटन 2013-14 के ₹33,000 करोड़ से बढ़कर 2024-25 में ₹2,86,000 करोड़ हो गया। 2013-14 तक कुल 1,660 करोड़ मानव-दिवस के बदले अब तक 3,210 करोड़ मानव-दिवस का सृजन हुआ। केंद्र से जारी धनराशि ₹2.13 लाख करोड़ से बढ़कर ₹8.53 लाख करोड़ हो गई और पूरे हुए कार्य 153 लाख से बढ़कर 862 लाख तक पहुँच गए। महिलाओं की भागीदारी 48% से बढ़कर 56.73% हो गई। अब 99% से अधिक फंड ट्रांसफर आदेश समय पर जारी होते हैं और लगभग 99% सक्रिय श्रमिक आधार पेमेंट ब्रिज से जुड़े हैं। ये सभी रुझान उपेक्षा नहीं, बल्कि निरंतर प्रतिबद्धता और बेहतर प्रदर्शन को दिखाते हैं। लेकिन समय के साथ यह भी साफ हो गया कि पुराने ढांचे में खुद कुछ बुनियादी कमजोरियां थीं-जैसे बीच-बीच में ही काम मिलना, बेरोजगारी भत्ता लागू कराने की कमजोर व्यवस्था, बिखरे हुए और असंगठित तरीके से संपत्ति/संसाधन निर्माण, और दोहराव व फर्जी प्रविष्टियों की गुंजाइश। ये कमजोरियां सूखे के समय, बड़े

पैमाने पर पलायन के दौर में और कोविड-19 जैसी आपदा के दौरान जमीन पर साफ दिखाई दीं। नए कानून के तहत की गई वित्तीय व्यवस्था को भी गलत तरीके से सरकारी जिम्मेदारी छोड़ने के रूप में गलत तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है। सच यह है कि केंद्र सरकार का योगदान बढ़ रहा है। केंद्र का हिस्सा ₹86,000 करोड़ से बढ़कर लगभग ₹2,95,000 करोड़ तक हो रहा है, जो ग्रामीण रोजगार के प्रति मजबूत और बढ़ते समर्थन को दर्शाता है। 60:40 की फंडिंग व्यवस्था वैसे ही है जैसी अन्य केंद्रीय सहायता प्राप्त योजनाओं में वर्षों से लागू है, जबकि पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों तथा जम्मू-कश्मीर के लिए 90:10 का अलग अनुपात रखा गया है। इसलिए यह किसी तरह की वित्तीय पीछे हटने का संकेत नहीं,बल्कि साझा जिम्मेदारी और जवाबदेही को और मजबूत करने का संकेत है।

न्याय और समानता सुनिश्चित करने के लिए धन आवंटन नियमों के आधार पर किया जाता है, और राज्यों का हिस्सा तय करने के लिए नियमों में दिए गए स्पष्ट व वस्तुनिष्ठ मानदंडों का पालन किया जाता है। राज्यों को सिर्फ लागू करने वाली एजेंसियों की तरह नहीं, बल्कि विकास के भागीदार के रूप में देखा गया है, जिन्हें कानूनी ढांचे के भीतर अपनी योजना अधिसूचित करने और लागू करने का अधिकार दिया गया है। लचीलापन भी बरकरार रखा गया है- प्राकृतिक आपदा या विशेष परिस्थितियों में राज्य अतिरिक्त छूट, अधिक प्रकार के कार्य और अस्थायी रूप से रोजगार बढ़ाने जैसी सिफारिशें कर सकते हैं। इस तरह नियम-आधारित आवंटन और परिस्थितियों के अनुसार लचीलापन, दोनों के बीच संतुलन बनाते हुए सहकारी संघवाद को मजबूत किया गया है। यह कानून राज्यों को यह अधिकार देता है कि वे पहले से ही एक वित्तीय वर्ष में कुल 60 दिनों की अवधि तय कर सकें, जो बुआई और कटाई जैसे कृषि के व्यस्त मौसमों को कवर करे, और उन दिनों के दौरान काम न कराया जाए। यह घोषणा ज़िला, ब्लॉक या ग्राम पंचायत स्तर पर, स्थानीय मौसम और कृषि परिस्थितियों के आधार पर अलग-अलग ढंग से की जा सकती है। इससे यह सुनिश्चित होगा कि बढ़ी हुई रोजगार गारंटी कृषि कार्यों में बाधा न बने, बल्कि उसके साथ संतुलन बनाकर चले।

सुशील भोले

कोंदा-भैरा के गोठ

हमर देश के अदालत मन म गीता के ही शपथ काबर देवाए जाथे जी भैरा.. रामायण या अउ आने पोथी पुराण के काबर नहीं?

-मुगल काल म ए व्यवस्था चालू होए रिहिसे अइसे बताए जाथे जी कोंदा.. लोगन ऊपर भरोसा देवाए खातिर ए परंपरा शुरू होय रिहिसे.. वो बखत हिंदू धर्म के अनुयायी मनला गीता, मुस्लिम मनला कुरान अउ ईसाई मनला बाइबिल के शपथ देवावँय.. ए ह दरबारी प्रथा रिहिसे.

-अच्छा.

-हव.. अँगरेज मन एमा बदलाव करिन अउ एला कानून के रूप देके 'इंडियन ओथ्स एक्ट 1873 म शामिल करिन.

-फेर मोर सवाल तो गीता म ही काबर हे ना?

-गीता म सिरिफ युद्ध या महाभारत के वर्णन नइए भलुक ए ह सत्य, धर्म अउ नैतिक आचरण के रद्दा बताथे.. गीता बताथे के मनखे ल हर परिस्थिति म सच्चाई, धर्म अउ न्याय के रद्दा म चलना चाही. एकरे सेती अदालत म गवाह ल गीता के शपथ देवाथें तेमा वो ह अपन बयान म सत्य के पालन करय अउ न्याय प्रक्रिया म ईमानदारी बरतय.

सुविचार- ऐसे करें संतुलित व्यक्तित्व

रत्न भूषण सिंह 'गहलौत'

ऐसा कहते हैं कि पीपल के पान (पत्ते), हाथी के कान और भ्रमित के भगवान- हिलते ही रहते हैं। अब इसे हम अपनी मानसिकता, दृष्टिकोण, सोच के साथ जोड़ें। इन तीनों का एक अर्थ होता है- माइंडसेट। हमारा माइंडसेट तीन तरह का हो सकता है- ग्रोथ, फिक्स्ड और बैलेंस्ड माइंडसेट। ग्रोथ माइंडसेट में लोग बहुत क्रिएटिव होते हैं, आशावादी होते हैं और उत्साह से भरे रहते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट में निराशा, उदासी, बेचैनी जल्दी घेर लेती है। इस मानसिकता के लोग जीवन में आगे नहीं जा पाते। और बैलेंस्ड माइंडसेट वाले शांत, प्रसन्न, सुनिश्चित, सफल होकर रहते हैं।

तो हमें यदि बैलेंस्ड माइंडसेट रखना है तो अपने मन पर काम करना होगा, क्योंकि मन पेंडुलम की तरह कभी एक अति पर जाता है, कभी दूसरी अति पर। वह कभी मध्य में नहीं रुकता। जिसने मन को रोक लिया, उसका पूरा व्यक्तित्व संतुलित होगा। और संतुलित व्यक्तित्व वाले व्यक्ति दुनिया और दुनिया बनाने वाले, दोनों को ठीक से पा लेते हैं।

साप्ताहिक शहर सत्ता

क्या रुकने वाली है रूस-यूक्रेन जंग?

ट्रंप से मिलेंगे जेलेंस्की; रूस के लिए क्या छोड़ेंगे-क्या मांगेंगे?

कोशिशें अब तक नाकाम रही हैं। अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के युद्ध को जल्द खत्म करने के दबाव और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की ओर से पीछे न हटने की चेतावनी के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की कुछ दबाव में दिखने लगे हैं। इसका असर यह हुआ है कि जेलेंस्की अब रविवार को ट्रंप के साथ एक बार फिर संघर्ष रुकवाने के लिए शांति समझौते के प्रस्ताव के साथ चर्चा करेंगे। रूस-यूक्रेन में युद्ध को खत्म करने के लिए अमेरिकी मध्यस्थता के साथ शांति वार्ता जारी है। वहीं दूसरी ओर जमीन पर जबरदस्त युद्ध भी चल रहा है। रूस ने बीते दिनों यूक्रेन के प्रमुख शहरों और सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं।

क्यों अहम है जेलेंस्की की ट्रंप से मुलाकात?

जेलेंस्की और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच होने वाली मुलाकात कई मायनों में अहम है। दरअसल, रूस-यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के लिए अमेरिका जोर-शोर से मध्यस्थता की कोशिशों में जुटा है। खासकर फरवरी में डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद से वे लगातार दोनों पक्षों को शांति योजना पर काम करने के लिए कहते रहे हैं। गौरतलब है कि अमेरिका में पिछले साल हुए राष्ट्रपति चुनाव से ठीक पहले तक ट्रंप कहते रहे थे कि वे रूस-यूक्रेन के बीच युद्ध रुकवा कर ही रहेंगे। ट्रंप इसके लिए फरवरी, अप्रैल, अगस्त में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेंलेंस्की और अगस्त में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात भी कर चुके हैं। हालांकि, जहां जेलेंस्की अब तक रूस के कब्जे वाली जमीन पर यूक्रेन की स्वायत्तता छोड़ने पर सहमत नहीं हुए हैं, तो वहीं पुतिन ने भी शांति समझौते के लिए जेलेंस्की से सीधी बात न करने, यूक्रेन की जमीन को न छोड़ने समेत कई शर्तें सामने रख दी हैं। ऐसे में ट्रंप फरवरी में राष्ट्रपति बनने के बाद से बीते 10 महीनों में युद्ध रुकवाने में पूरी तरह असफल रहे हैं।

कूटनीतिक उच्च-स्तरीय बैठकों का दौर जारी

यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की आज फ्लोरिडा में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करने वाले हैं। इस बैठक का मकसद अमेरिका की ओर से प्रस्तावित 20-सूत्रीय शांति योजना पर चर्चा और इसके अधिकतर मुद्दों पर सहमति बनाना होगा। जेलेंस्की ने घोषणा की है कि यह 20-सूत्रीय शांति योजना के 90 फीसदी बिंदुओं पर तैयार हैं। उन्होंने उम्मीद जताई है कि नए साल से पहले बहुत कुछ तय किया जा सकता है। जेलेंस्की ने रूस-यूक्रेन संघर्ष रुकवाने की कोशिशों में जुटे अमेरिकी प्रतिनिधियों (स्टीव व्हिटकॉफ और जैरेड कुश्नर) के साथ हुई बातचीत को सकारात्मक बताया है, जिससे शांति समझौते के प्रारूप, बैठकें और समय के संदर्भ में नए विचार मिले हैं।

क्या हैं रूस की मांग?

1. यूक्रेन के क्षेत्र पर पूर्ण कब्जा

पुतिन शासन की मांग है कि वह कोई भी समझौता सिर्फ यूक्रेन में चुनाव के बाद ही कर सकता है। यह रूस की प्राथमिक मांग है। रूस चाहता है कि समग्र तौर पर यूक्रेन के डोनबास क्षेत्र यानी डोनेत्स्क और लुहांस्क पर उसका नियंत्रण मान्यता दी जाए। यूक्रेनी सेना की डोनबास से पूर्ण वापसी उसकी केंद्रीय शर्त है। रूस संकेत देता रहा है कि ऐसा न हुआ तो वह बल प्रयोग जारी रखेगा। रूस चाहता है कि उसके यूक्रेन के आंशिक रूप से कब्जे वाले अन्य क्षेत्रों में भी नियंत्रण को मान्यता दी जाए। इनमें खेरसॉन, जैपोरिज्झिया और क्रीमिया जैसे इलाके शामिल हैं, जिन पर रूस अपने कब्जे को स्थायी करना चाहता है।

2. यूक्रेन की सैन्य-कूटनीतिक क्षमता में कटौती

यूक्रेन की प्रस्तावित 8,00,000 सैनिकों वाली सेना में कमी। भारी हथियारों, मिसाइलों और लंबी दूरी की क्षमताओं पर सीमाएं। यूक्रेन की नाटो सदस्यता पर रोक और तटस्थता की मांग। नाटो-स्तरीय (आर्टिकल-5 जैसी) सुरक्षा गारंटी का विरोध। यूरोपीय देशों की किसी भी शांति-रक्षक बल की तैनाती अस्वीकार। सीमावर्ती क्षेत्रों में पश्चिमी सैन्य ढांचे का विरोध।

3. जैपोरिज्झिया परमाणु संयंत्र पर नियंत्रण

संयंत्र के आसपास की सुरक्षा रूस के नियंत्रण में देने की मांग। अमेरिकी या किसी तीसरे पक्ष के संचालन पर आपत्ति।

4. आर्थिक छूट देने की मांग

रूस ने शांति समझौते के बदले आर्थिक प्रतिबंधों में राहत की भी मांग की है।

क्या है यूक्रेन की मांग?

1. क्षेत्रीय संप्रभुता की बहाली

कब्जाए गए यूक्रेनी क्षेत्रों से रूसी सेना की वापसी।

डोनबास, जैपोरिज्झिया, खेरसॉन और क्रीमिया की स्थायी वापसी। किसी भी क्षेत्रीय रियायत पर अंतिम फैसला यूक्रेनी जनमत संग्रह से।

2. मजबूत सुरक्षा गारंटी

अमेरिका, नाटो और यूरोपीय देशों से नाटो के अनुच्छेद 5 जैसी सुरक्षा गारंटी। यूक्रेन की नाटो और यूरोपीय संघ में शामिल होने की संभावना खुली रहे। शांति काल में भी 8 लाख सैनिकों तक की सेना बनाए रखने की छूट। आत्मरक्षा के लिए आर्थिक मदद, आधुनिक हथियार और सैन्य ढांचा। सीमावर्ती और संघर्ष वाले क्षेत्रों में डिमिलिट्राइज्ड जोन (असैन्य क्षेत्र)।

3. जैपोरिज्झिया परमाणु ऊर्जा संयंत्र

संयंत्र और उसके आसपास से रूसी सेना की वापसी। संयंत्र का नियंत्रण यूक्रेन या किसी तीसरे पक्ष के पास।

4. न्याय और जवाबदेही

युद्ध अपराधों की अंतरराष्ट्रीय जांच। रूस से क्षतिपूर्ति की मांग। पुनर्निर्माण और आर्थिक सहायता।

जम्मू-कश्मीर के बर्फीले इलाकों में 30 से 35 आतंकी एक्टिव

एजेंसियों के अलर्ट के बाद सेना का ऑपरेशन शुरू

श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर के डोडा और किश्तवाड़ इलाकों में 30-35 पाकिस्तानी आतंकियों के छिपे होने के इनपुट से भारतीय सेना के कान खड़े हो गए हैं. भारतीय सेना ने चिलाए कलां मौसम के बावजूद, इन बर्फीले इलाकों में आतंकियों के खिलाफ सघन तलाशी अभियान छेड़ दिया है. इंटेलिजेंस एजेंसियों ने इन इलाकों में आतंकियों के छिपे होने की जानकारी सेना से साझा की है.भारतीय सेना के सूत्रों के मुताबिक, सर्दियों के मौसम में आतंकी घटनाओं में कमी देखने को मिलती है, लेकिन इस बार सेना ने अपनी रणनीति में तब्दीली करते हुए सर्दियों में भी अपने ऑपरेशन तेज कर दिए हैं. इसके लिए सेना के साथ-साथ जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ की मदद ली गई है.खुफिया जानकारी के मुताबिक, चिलाए कलां की सर्दियों के चलते आतंकी, डोडा और किश्तवाड़ के ऊंचाई वाले इलाकों में छिपने के लिए पहुंच गए हैं. ऐसे में काउंटर-टेररिज्म ऑपेशन्स के लिए भारतीय सेना की राष्ट्रीय राइफल्स (RR) की यूनिट्स को इन ऊंचाई और बेहद खतरनाक इलाकों में तैनात किया गया है. इन यूनिट्स को ड्रोन और थर्मल इमेंजिग उपकरणों से लैस किया गया है.जम्मू-कश्मीर के चिलाए कलां मौसम में हड्डियों को गलाने वाले ठंड पड़ती है. ये मौसम अमूमन 21 दिसंबर से 31 जनवरी तक रहता है. इस दौरान, डोडा-किश्तवाड़ के ऊंचाई वाले इलाकों में जबरदस्त बर्फबारी होती है।

पनडुब्बी INS वाघशीर में सवार हुईं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू

नई दिल्ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने रविवार को पश्चिमी तट पर भारतीय नौसेना की अग्रिम पंक्ति की पनडुब्बी आइएनएस वाघशीर से भारतीय समुद्री क्षेत्र का दौरा किया। मुर्मु पनडुब्बी से समुद्री दौरा करने वाली दूसरी राष्ट्रपति बन गईं। इससे पहले, फरवरी 2006 में एपीजे अब्दुल कलाम पहले राष्ट्रपति बने थे जिन्होंने पनडुब्बी की सैर का अनुभव किया था।

भारतीय नौसेना करवार अड्डे का विकास भारत के हिंद महासागर क्षेत्र में दीर्घकालिक सुरक्षा हितों को ध्यान में रखते हुए कर रही है। अधिकारियों ने बताया कि नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के. त्रिपाठी भी करवार नौसेना अड्डे से कलवरी श्रेणी की पनडुब्बी में राष्ट्रपति मुर्मु के साथ उपस्थित रहे। राष्ट्रपति सशस्त्र बलों की सर्वोच्च कमांडर भी हैं। राष्ट्रपति सचिवालय ने इंटरनेट मीडिया पर पोस्ट किया, 'राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने करवार नौसेना अड्डे पर भारतीय नौसेना की स्वदेशी कलवरी श्रेणी की पनडुब्बी आइएनएस वाघशीर में प्रवेश किया।' राष्ट्रपति ने नौसेना की वर्दी पहन रखी थी और पनडुब्बी में प्रवेश करने से पहले नौसेना के कर्मियों से हाथ हिलाया। नौसेना के अधिकारियों के अनुसार आइएनएस वाघशीर, पी75 स्कार्पीन परियोजना की छठी और अंतिम पनडुब्बी है, जिसे जनवरी में नौसेना में शामिल किया गया था। यह दुनिया की सबसे शांत और बहुउपयोगी डीजल-इलेक्ट्रिरक पनडुब्बियों में से एक है।

उन्नाव रेप केसः कुलदीप सेंगर की सजा निलंबित किए जाने के खिलाफ सुको में सुनवाई

नई दिल्ली। उन्नाव रेप केस को लेकर शनिवार (27 दिसंबर, 2025) को एक बड़ा अपडेट सामने आया है. इस मामले में

दोषी कुलदीप सिंह सेंगर की सजा सस्पेंड करने के खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई होगी. चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी. कुलदीप सिंह सेंगर को जमानत देने के फैसले के विरोध में सामाजिक कार्यकर्ता योगिता भयाना और कांग्रेस नेता मुमताज पटेल ने संसद भवन के बाहर विरोध प्रदर्शन किया था, जहां से दिल्ली पुलिस ने योगिता-मुमताज समेत कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया है. वहीं, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बुधवार (24 दिसंबर, 2025) को रेप केस की पीड़िता और उसके परिवार से मुलाकात की. इस मुलाकात के दौरान पीड़िता और उसके परिवार ने कांग्रेस नेता के सामने तीन मांगें भी रखी. इसके बाद राहुल गांधी ने इस मुद्दे को ध्यान में लेने का वादा किया और उन्होंने पीड़िता को आश्वासन दिया कि वे उन्हें न्याय दिलवाएंगे।

पाकिस्तान के राष्ट्रपति जरदारी का कबूलनामा

ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बंकर में छिपने की नौबत आ गई थी

नई दिल्ली। वैश्विक मंच पर पाकिस्तान एक बार फिर न सिर्फ बेनकाब हुआ है, बल्कि इसे शर्मिंदगी भी उठानी पड़ी है क्योंकि इसने मई में भारत द्वारा किए गए रणनीतिक और सटीक हमलों के प्रभाव को स्वीकार किया है। पहलगाम आतंकी हमले के प्रतिशोध में आपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के खिलाफ भारत की त्वरित और सटीक जवाबी सैन्य कार्रवाई से पड़ोसी देश न केवल सामरिक दृष्टि से थर्रा उठा था, बल्कि उसका शीर्ष नेतृत्व भी बेहद खौफजदा था। पाकिस्तान में डर का यह आलम था कि राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी को बंकर में शरण लेने की सलाह दी गई थी। इस बात की तस्दीक एक कार्यक्रम में स्वयं जरदारी ने की। उन्होंने शनिवार को स्वीकार किया कि मई में तनाव बढ़ने के बाद नई दिल्ली के जवाबी हमलों के दौरान उनके सैन्य सचिव ने उन्हें सुरक्षा के लिए तुरंत बंकर में जाने की सलाह दी थी। यह भारतीय सैन्य कार्रवाई के दौरान पाकिस्तान के शीर्ष नेतृत्व में व्याप्त भय को उजागर करता है।

भारतीय ड्रोन ने सैन्य प्रतिष्ठान को नुकसान पहुंचाया

डार विदेश मंत्री एवं उप प्रधानमंत्री इशाक डार ने भी शनिवार को साल के अंत में आयोजित होने वाले प्रेस ब्रीफिंग के दौरान पुष्टि की कि भारत ने रावलपिंडी के चकाला स्थित उनके नूर खान एयर बेस को निशाना बनाया था, जिससे उनकी सैन्य प्रतिष्ठानों को नुकसान पहुंचा और वहां तैनात कर्मी घायल हो गए। उन्होंने कहा कि भारत ने 36 घंटों के भीतर पाकिस्तानी क्षेत्र में कई ड्रोन भेजे थे और एक ड्रोन ने सैन्य प्रतिष्ठान को नुकसान पहुंचाया जो आपरेशन के पैमाने और सटीकता को उजागर करता है। विदेश मंत्री ने दावा किया कि उन्होंने (भारत ने) पाकिस्तान की ओर ड्रोन भेजे। 36 घंटों में कम से कम 80 ड्रोन भेजे गए, हम 80 में से 79 ड्रोनों को रोकने में सफल रहे, और केवल एक ड्रोन ने सैन्य प्रतिष्ठान को नुकसान पहुंचाया और हमले में कर्मी भी घायल हुए। पाकिस्तान और गुलाम कश्मीर में नौ आतंकी शिविर भी ध्वस्त हुए इस टिप्पणी से डार ने मई में पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों पर भारत द्वारा की गई रणनीतिक कार्रवाई को स्वीकार किया। पहलगाम हमले में 26 नागरिकों की हत्या के बाद अपनी कार्रवाई में 'भारत के सशस्त्र बलों ने पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों पर बेहद सटीक हमले किए'। चकलाल स्थित पाकिस्तानी वायुसेना बेस नूर खान को भारी नुकसान पहुंचा। सेटेलाइट तस्वीरों में रावलपिंडी स्थित नूर खान वायु सेना, सरगोधा स्थित पीएएफ बेस मुशफ, भोलारी वायु सेना और जैकबबाद स्थित पीएएफ बेस शाहबाज सहित चार पाकिस्तानी वायु अड्डों को हुए नुकसान को दर्शाया गया है। पाकिस्तान और गुलाम जम्मू-कश्मीर में नौ आतंकी शिविरों को भी ध्वस्त कर दिया गया।

टीम इंडिया ने लगाया जीत का चौका

श्रीलंका के खिलाफ टी20 सीरीज में 4-0 से आगे

भारत ने श्रीलंका को 30 रनों से हराकर चौथा टी20 मैच जीत लिया है. तिरुवनंतपुरम में खेले गए इस मैच में भारतीय टीम ने पहले ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 221 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया था. ये अंतर्राष्ट्रीय महिला टी20 क्रिकेट इतिहास में भारत का सबसे बड़ा स्कोर रहा. जवाब में श्रीलंकाई टीम अच्छी शुरुआत के बावजूद निर्धारित 20 ओवरों में 191 रन ही बना सकी. अब तक सीरीज के चारों मैच भारत ने जीते हैं. भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 221 रन बनाए थे. स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा ने 162 रनों की ओपनिंग पार्टनरशिप कर बड़े स्कोर की नींव रखी थी. स्मृति मंधाना ने 48 गेंद में 80 रन बनाए थे, वहीं शेफाली वर्मा ने 79 रनों की पारी खेली. रिचा घोष ने भी सुर्खियां बटोरीं, जिन्होंने 16 गेंद में 40 रनों की तूफानी पारी खेली.

222 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने आई श्रीलंका को हसीनी परेरा और कप्तान चमारी अटापट्टू ने पावरप्ले समाप्त होने से पहले ही 59 रनों की सलामी साझेदारी कर बढ़िया शुरुआत दिलाई थी. एक समय श्रीलंका ने केवल एक विकेट के नुकसान पर 116 रन बना लिए थे. इसी समय कप्तान अटापट्टू 52 रन बनाकर आउट हो गईं. उसके बाद कोई बल्लेबाज बड़ी पारी नहीं खेल सका और जरूरी रन रेट भी आसमान को छूने लगा था. कप्तान अटापट्टू के आउट होने के बाद ही श्रीलंका की जीत की उम्मीद फीकी पड़ने लगी थी. आलम यह था कि अंतिम 7 ओवरों में उसे जीत के लिए 106 रन बनाने थे. एक और गौर करने वाला विषय यह है कि श्रीलंका चाहे ये मैच 30 रनों से हार गई हो, लेकिन 191 रन अंतर्राष्ट्रीय टी20 क्रिकेट में उसका सबसे बड़ा स्कोर है.

दो खिलाड़ी होंगे बाहर अय्यर-गिल की वापसी

नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट टीम की अगली इंटरनेशनल सीरीज न्यूजीलैंड के खिलाफ है. भारत दौरे पर शुरुआत 3 वनडे मैचों की सीरीज से होगी, जिसका पहला मुकाबला 11 जनवरी को वडोदरा के बीसीए स्टेडियम में होगा. बीसीसीआई जनवरी के पहले हफ्ते में टीम का एलान कर सकता है. टीम में 2 बदलाव संभव है.

भारतीय टेस्ट और वनडे टीम के कप्तान शुभमन गिल दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट में चोटिल हुए थे. उनके पैर में चोट लगी थी, जिसके बाद वह टेस्ट और फिर पूरी वनडे सीरीज से बाहर हुए. हालांकि उन्होंने टी20 सीरीज से वापसी की, लेकिन प्रदर्शन खराब रहा. इसी का नतीजा रहा कि उन्हें टी20 वर्ल्ड कप के लिए टीम में नहीं चुना गया.

श्रेयस अय्यर की होगी वापसी?

श्रेयस अय्यर की बात करें तो वह ऑस्ट्रेलिया दौरे पर बुरी तरह चोटिल हुए थे, वह अभी बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में रिहैब प्रक्रिया से गुजर रहे हैं. अच्छी बात ये हैं कि अय्यर नेट पर बल्लेबाजी का अभ्यास शुरू कर चुके हैं, जो उनके कमबैक की दिशा में बहुत ही अच्छी खबर है.ईशान किशन और देवदत्त पडिक्कल विजय हजारे ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अभी उनके लिए टीम में जगह नजर नहीं आ रही. ईशान को टी20 वर्ल्ड कप और न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए चुना गया है, लेकिन वनडे में उन्हें इंतजार करना पड़ सकता है. दूसरी तरफ विजय हजारे में लगातार 2 शतक लगाने के बावजूद पडिक्कल को टीम में चुना जाए, ऐसा मुश्किल लग रहा है.

तिलक और जुरेल होंगे बाहर

शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर के आने से तिलक वर्मा और ध्रुव जुरेल को बाहर होना पड़ेगा. 2 विकेटकीपर के रूप में टीम में केएल राहुल और ऋषभ पंत शामिल होंगे, तिलक वर्मा को भी बाहर जाना पड़ सकता है, जो ऋतुराज गायकवाड़ के बैकअप थे.

पहली बार 1.40 लाख पर पहुंचा सोने का भाव

नई दिल्ली। साल खत्म होने वाला है, लेकिन सोने की कीमतें कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं. 24 कैरेट में

10 ग्राम सोने का भाव 1.40 लाख तक पहुंच गया है. ऐसे में यह साल सोने की कीमतों के लिए ऐतिहासिक साबित होता दिख रहा है.. अब लोगों को इस बात की चिंता सताने लगी है कि क्या 2026 में भी कीमतों में यही तेजी जारी रहेगी? जेपी मॉर्गन के विश्लेषकों का कहना है कि अगले साल दिसंबर तक सोने की कीमत 5000 डॉलर प्रति औंस (158485 रुपये प्रति 10 ग्राम) तक जा सकती है. गोल्डमैन सैक्स के मुताबिक, अगले साल सोने की कीमतें लगभग 36 परसेंट बढ़ सकती हैं और यह 5000 डॉलर प्रति औंस तक पहुंच सकती हैं. मौजूदा एक्सचेंज रेट के हिसाब से यह लगभग 1,58,213 रुपये प्रति 10 ग्राम होगा।

2025 में बंद हुए भारत के ये बड़े स्टार्टअप

नई दिल्ली। साल 2025 स्टार्टअप्स के लिए उतार-चढ़ाव भरा रहा. जहां एक तरफ कई कंपनियों ने शुरुआत की तो, वहीं दूसरी ओर कुछ पुराने और जाने-माने स्टार्टअप्स को अपना सफर रोकना पड़ा. आइए जानते हैं, 2025 में कौन-कौन से बड़े स्टार्टअप्स बंद हुए....

1. Hike

Hike की शुरुआत बेहद शानदार रही थी. इसे WhatsApp और टेलीग्राम जैसे ग्लोबल मैसेजिंग प्लेटफॉर्म को टक्कर देने वाला बताया गया था. Hike की शुरुआत 2012 में भारती मित्तल के बेटे केविन मित्तल ने की थी. साल 2021 में कॉम्पिटीशन के कारण कंपनी की मैसेजिंग सर्विस बंद हो गई. इसके बाद कंपनी ने मनी गेमिंग प्लेटफॉर्म पर फोकस किया. सितंबर 2025 में सरकार के द्वारा रियल मनी गेमिंग ऐप्स पर पूरी तरह से पाबंदी लगाने के बाद कंपनी ने अपना ऑपरेशंस बंद कर दिया है.

2. Dunzo

डंजो भारत में हाइपरलोकल डिलीवरी सेगमेंट में शुरुआती कंपनियों में से एक रही है. साल 2022 में कंपनी ने रिलायंस रिटेल से 24 करोड़ डॉलर की बड़ी फंडिंग जुटाई थी. हालांकि, समय के साथ बाजार में कई दूसरे खिलाड़ी आए.जेप्टो, स्विगी इंस्टामार्ट और ब्लिंकइट जैसे खिलाड़ियों के आने से डंजो की पकड़ बाजार में कमजोर हो गई. 2025 में कंपनी का सफर समाप्त हो गया.

3. Otipy

Otipy की शुरुआत साल 2020 में लॉकडाउन के दौरान हुई थी. यह एक सब्सक्रिप्शन बेस्ड ग्रोसरी डिलीवरी सर्विस देने वाली कंपनी थी. फंड की कमी होने के कारण साल 2025 में यह स्टार्टअप बंद हो गया.

4. BluSmart

ब्लूस्मार्ट की शुरुआत 2019 में हुई थी, यह ओला उबर की तरह कैब सर्विस देने वाली कंपनी थी. कंपनी की ओर से ईवी और सैलरी बेस्ड ड्राइवर सर्विस का वादा किया गया था. हालांकि, वित्तीय गड़बड़ियों के आरोप के कारण कंपनी को नुकसान हुआ।

पोलार्ड बने टी20 के 'सिक्सर किंग'

नई दिल्ली। इंटरनेशनल लीग T20 (ILT20) में MI एमिरेट्स का दबदबा जारी है। सीजन के 29वें मैच में

एमआई एमिरेट्स ने दुबई कैपिटल्स को 8 विकेट से हराया। पोलार्ड टी20 क्रिकेट के इतिहास में कप्तान के तौर पर 300 छक्के पूरे करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने धोनी और रोहित जैसे दिग्गजों को पीछे छोड़ते हुए यह आंकड़ा छुआ है। जहां टीम को आखिरी 6 ओवर में 40 रन की दरकार थी, तब पोलार्ड ने अटैकिंग अंदाज में बैटिंग कर चौके-छक्कों की बौछार लगाई। एक ओवर में उन्होंने 30 रन ठोक डाले और 16.4 ओवर में ही टीम को 123 रन का लक्ष्य हासिल करने में मदद की। इस दौरान पोलार्ड ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी अपने नाम किया। दरअसल, कीरोन पोलार्ड ने टी20 क्रिकेट में एक ऐसा रिकॉर्ड बना लिया है, जिसे तोड़ना रोहित शर्मा और महेंद्र सिंह धोनी जैसे दिग्गजों के लिए भी नामुमकिन नजर आ रहा है। अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में दुबई कैपिटल्स के खिलाफ खेले गए ।LT20 मैच में पोलार्ड ने ना केवल अपनी टीम को जीत दिलाई, बल्कि इतिहास के पन्नों पर अपना नाम दर्ज कराया।

सलामत है गंभीर की कुर्सी

नई दिल्ली। गौतम गंभीर जबसे हेड कोच बने हैं, तभी से टेस्ट फॉर्मेट में टीम इंडिया का प्रदर्शन खराब रहा है.भारत ने 2025 में 10 टेस्ट खेले, जिनमें उसे केवल चार मुकाबलों में जीत मिली, पांच हार झेलनी पड़ी थीं और एक मैच ड्रॉ रहा. इसी बीच खबर सामने आई कि गौतम गंभीर की नौकरी खतरे में है क्योंकि BCCI ने अनौपचारिक तरीके से वीवीएस लक्ष्मण से बात की है. मगर बीसीसीआई ने इन अफवाहों को खारिज कर दिया है.र पीटीआई के मुताबिक लक्ष्मण ने हेड कोच के ऑफर को ठुकरा दिया था.न्यूज एजेंसी ANI से बातचीत में बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने कहा, "जो भी खबर वायरल है, वह सब झूठ है. ये खबर काल्पनिक है।

आधार से कार तक की कीमतों में होगा बदलाव

1 जनवरी 2026 से होंगे कई बड़े बदलाव

नए साल यानी 2026 में कई बदलाव देखने को मिलेंगे. इस साल कई आर्थिक नियम बदले जाएंगे. इससे आम नागरिक की जेब पर सीधा असर पड़ेगा. इनमें एलपीजी गैस, पैन, आधार समेत कई तमाम चीजें हैं. आइए जानते हैं किन नियमों में बदलाव होगा. नए साल में बदलाव की कड़ी में यूपीआई, सिम, मैसेंजिग नियम में बदलाव देखने को मिलेगा. इस सिलसिले में यूपीआई और डिजिटल पैमेंट से जुड़े नियम सख्त किए जाएंगे. फ्रॉड से बचने के लिए सिम के वेरिफिकेशन के नियम को और सख्त बनाया जाएगा. इनमें कुछ मैसेंजिग एप जैसे व्हाटसएप, टेलीग्राम पर लगाम लगाने की तैयारी है, ताकि इससे होने वाले फ्रॉड को कम किया जा सके. इनके अलावा पैन और आधार को लिंक करने की तारीख भी इस दिसंबर में खत्म हो जाएगी. अगर इन्हें लिंक नहीं किया जाता है, तो 1 जनवरी से ये निष्क्रिय हो जाएंगे. इससे आप आईटीआर रिफंड, रिसिप्ट और बैंकिंग का लाभ नहीं ले पाएंगे. साथ ही सरकारी योजनाओं से मिलने वाले लाभ से वंचित रह जाएंगे. सरकार इस साल आईटीआर से जुड़े नियम भी बदलने वाली है. सरकार अप्रैल में नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 लागू करेगी. यह इनकम टैक्स एक्ट 1961 की जगह लागू होगा. इसी साल 8वें वेतन आयोग के प्रभावी होने के कयास लगाए जा रहे हैं. 31 दिसंबर से सातवां वेतन आयोग निष्प्रभावी होगा.

बैंकिंग सिस्टम में होंगे ये बड़े बदलाव

एक बदलाव और बैंकिंग सिस्टम में किया जाएगा. यहां एसबीआई, पंजाब नेशनल बैंक और एचडीएफस बैंक में लोन दरों को कम किया जाएगा. फैसला 1 जनवरी से लागू हो जाएगा. इस तरह से जनवरी से नई फिक्स्ड डिपॉजिट ब्याज दरें लागू होंगी.

LPG सिलेंडर की कीमतों में होगा बदलाव

एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में भी बदलाव देखने को मिलेगा. 1 जनवरी से एलपीजी के रेट में कम या ज्यादा हो सकते हैं. इसका असर आपके बजट पर पड़ेगा. हाल ही में दिसंबर से गैस सिलेंडर के रेट 10 रुपये कम किए गए थे. इनके अलावा सीएनजी-पीएनजी, एटीएफ (हवाई जहाज का फ्यूल) के दामों में भी बदलाव देखने को मिलेगा.

साप्ताहिक शहर सत्ता

नए साल में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का होगा चुनाव, छत्तीसगढ़ की भी रहेगी अहम भूमिका

रायपुर। भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव नए साल में 20 जनवरी से पहले होने की संभावना है। चुनाव की प्रक्रिया 18 जनवरी से प्रारंभ होने के संकेत हैं। लंबे इंतजार के बाद भाजपा के राष्ट्रीय संगठन ने भाजपा के प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है। संभावना यही है कि नितिन नवीन को ही पूर्णकालिक अध्यक्ष बनाया जाएगा। इस बार नए अध्यक्ष के चुनाव में छत्तीसगढ़ की भी भूमिका भी अहम रहेगी।

चुनाव में प्रदेश को भी भागीदारी करने का पूरा मौका मिलेगा। प्रदेश में इस बार भाजपा प्रदेश संगठन के चुनाव पूरे होने के साथ राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों का भी चुनाव हो गया है। प्रदेश के राष्ट्रीय परिषद के सदस्य ही राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के नामांकन में प्रस्तावक और समर्थक बनेंगे। कई राज्यों की तरफ से नामांकन भरा जाएगा। छत्तीसगढ़ की तरफ से भी एक नामांकन भरे जाने की संभावना है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव से पहले देशभर के राज्यों में भाजपा संगठन के चुनाव कराए गए। छत्तीसगढ़ में ही सबसे पहले इस साल 17 जनवरी को प्रदेश संगठन के चुनाव पूरे हुए, तब यहां पर भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष के साथ ही राष्ट्रीय परिषद के 17 सदस्यों का चुनाव कराया गया। पूरे देश में छत्तीसगढ़ संगठन चुनाव पूरा कराने वाला पहला राज्य बना। इसके बाद दूसरे राज्यों के चुनाव पूरे हुए। देश के ज्यादातर राज्यों में संगठन के चुनाव हो चुके हैं। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना है।

प्रदेश से 17 राष्ट्रीय परिषद के सदस्य

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में कई राज्यों के राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों से नामांकन फार्म में प्रस्तावक और समर्थक के रूप में हस्ताक्षर कराए जाते हैं। पिछली बार जब 2020 में राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में जेपी नड्डा अध्यक्ष बने, तब छत्तीसगढ़ में प्रदेश संगठन का चुनाव पूरा न होने के कारण छत्तीसगढ़ को इसमें भागीदारी का मौका नहीं मिला था, लेकिन इस बार चुनाव पूरे होने के कारण छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय परिषद के 17 सदस्यों के साथ ही भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष किरण देव को भी प्रस्ताव और समर्थक बनने का मौका मिलेगा। प्रदेश में जो राष्ट्रीय परिषद के सदस्य बने हैं, उनमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, डिप्टी सीएम अरुण साव, विजय शर्मा, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सरोज पांडेय, लता उसेंडी, केंद्रीय मंत्री तोखन साहू, सांसद बृजमोहन अग्रवाल, संतोष पांडेय, विजय बघेल, रूपकुमारी चौधरी, राज्य सभा सांसद देवेंद्र राजा प्रताप सिंह, विधायक विक्रम उसेंडी, पुन्नूलाल मोहिले, प्रदेश के मंत्री दयालदास बघेल, केदार कश्यप, पूर्व विधायक ननकी राम कंवर और खूबचंद पारख शामिल हैं। इनको जहां प्रस्तावक और समर्थक बनने का मौका मिलेगा, वहीं अध्यक्ष का चुनाव होने की स्थिति में इनको मतदान का भी अधिकार मिलेगा।

भाजयुमो की प्रदेश कार्यकारिणी से बाहर होंगे ओवरएज पदाधिकारी

रायपुर। भारतीय जनता युवा मोर्चा की प्रदेश कार्यकारिणी में आधा दर्जन से ज्यादा पदाधिकारी ओवरएज बनाए गए हैं। भाजपा के राष्ट्रीय संगठन ने किसी भी हाल में अंडर 35 को ही पदाधिकारी बनाने का फरमान जारी किया है, इसके बाद भी ओवरएज को पदाधिकारी बना दिया गया है। ओवरएज पदाधिकारियों के बारे में बताया जा रहा है कि ये उम्र का गलत दस्तावेज देकर पदाधिकारी बन गए हैं। अब भाजयुमो के प्रदेशाध्यक्ष राहुल टिकरिया का कहना है कि शिकायत मिली है कि ओवरएज पदाधिकारी बन गए हैं। इनके दस्तावेज जांचे जा रहे हैं जो भी ओवरएज पदाधिकारी बने हैं, उनको बाहर किया जाएगा। किसी भी ओवरएज को पद में नहीं रखा जाएगा। भाजयुमो की प्रदेश कार्यकारिणी के साथ ही जिलाध्यक्षों को लेकर भाजपा के राष्ट्रीय संगठन से मिले निर्देश के बाद भाजपा के प्रदेश संगठन ने स्पष्ट रूप से यह निर्देश जारी किया था कि भाजयुमो की प्रदेश कार्यकारिणी में 35 साल से ज्यादा और जिलाध्यक्ष 33 साल से ज्यादा के नहीं होने चाहिए। इस निर्देश के बाद भी प्रदेश कार्यकारिणी में करीब आठ पदाधिकारियों के ओवरएज होने की बात सामने आ रही है।

जिलाध्यक्षों की जिम्मेदारी थी

भाजयुमो के प्रदेश पदाधिकारियों और जिलाध्यक्षों के लिए भाजयुमो के पास जो भी नाम भेजे गए हैं सभी नाम जिलों से आए हैं। भाजपा संगठन के जिलाध्यक्षों को ही यह जिम्मेदारी दी गई थी कि वे जिन भी पदाधिकारियों के नाम भाजयुमो को भेजें उनके उम्र के दस्तावेज जांच कर ही नाम भेजें। जानकारों का कहना है कि जिनके भी नाम भाजयुमो को भेजे गए हैं, उनके दस्तावेज जिलों में जांच गए हैं, लेकिन कुछ लोगों ने पद पाने के लिए उम्र के गलत दस्तावेज दिए हैं। इसकी शिकायत होने पर इस बात का खुलासा हुआ है। अब इसकी जांच में कुछ पदाधिकारी ओवरएज पाए गए हैं।

पवन साय को बंगाल चुनाव में 56 विधानसभाओं की जिम्मेदारी

रायपुर। भाजपा के प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय को बंगाल चुनाव के लिए 56 विधानसभाओं के एक जोन की जिम्मेदारी दी गई है। वे चौथी बार वहां के दौरे पर गए हैं और विधानसभाओं की बैठक लेकर वहां पर जीत की रणनीति बना रहे हैं। बंगाल में अलग-अलग जोन बनाकर आधा दर्जन राज्यों के संगठन महामंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई है।

बिहार चुनाव में ऐतिहासिक जीत के बाद अब भाजपा के राष्ट्रीय संगठन का बड़ा फोकस बंगाल चुनाव पर है। अगले साल मार्च-अप्रैल में वहां पर चुनाव संभावित है। भाजपा ने अभी से इसको लेकर तैयारी प्रारंभकर दी है। वैसे भी भाजपा हमेशा से किसी भी राज्य में चुनाव से काफी पहले तैयारी प्रारंभकर देती है। बिहार चुनाव में भी भाजपा ने काफी पहले से तैयारी की थी। प्रदेश के क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल को वहां पर 50 विधानसभाओं की जिम्मेदारी दी गई थी। श्री जामवाल बिहार में चार माह तक रहे और अपनी जिम्मेदारी वाली विधानसभाओं में लगातार बैठकें लेकर रणनीति बनाने का काम किया। इसका परिणाम यह रहा कि 50 सीटों में से 25 सीटों में भाजपा के प्रत्याशी मैदान में उत्तारे गए तो इसमें से 23 सीटों में भाजपा के प्रत्याशियों को जीत मिली। भाजपा का राष्ट्रीय संगठन लगातार प्रदेश के नेताओं पर भरोसा कर रहा है। बिहार चुनाव में प्रदेश के जिन भी नेताओं को वहां पर विधानसभाओं की जिम्मेदारी दी गई थी, उन सभी में भाजपा के प्रत्याशी जीते।

महंगी बिजली के बिल नहीं पटा पा रहे उपभोक्ता, कनेक्शन कट रहेः कांग्रेस

बिजली बिल ने आम जनता का बजट बिगाड़ दिया

रायपुर। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा, तीन माह से आ रहे बेतहाशा बढ़े बिजली बिल से राज्य का हर नागरिक परेशान है। 200 यूनिट हॉफ बिजली योजना से भी कोई राहत नहीं है।

कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि सरकार भूपेश सरकार के समय शुरू की गई बिजली बिल हॉफ योजना को फिर शुरू करे, ताकि जनता को बढ़े बिजली बिल में कुछ राहत मिल सके। बिजली बिल हॉफ योजना बंद करने के कारण जनता बिजली के बिल नहीं पटा पा रही, उनका कनेक्शन काटा जा रहा। अकेले रायपुर में 2000 लोगों के कनेक्शन कटे हैं। प्रदेश में हजारों उपभोक्ताओं का बिजली कनेक्शन काट दिया गया है। श्री शुक्ला ने कहा, सरकार की नाकामी लापरवाही और मुनाफाखोरी वाली नीति के कारण प्रदेश के लोगों के लिए बिजली कटौती और मंहगी बिजली बड़ी समस्या बन गई है। राज्य बनने के बाद प्रदेश में बिजली के दाम सबसे ज्यादा वर्तमान समय में हैं। सरकार ने 400 यूनिट बिजली बिल हॉफ योजना को बंद कर दिया, जिससे लोगों के बिजली का बिल दोगुना से भी अधिक आ रहा। महंगी बिजली के बाद भी सरकार जनता को चौबीस घंटे बिजली नहीं उपलब्ध करवा पा रही। ग्रामीण क्षेत्र में आठ-नौ घंटे तक बिजली कटौती से जनता परेशान हो रही, लोग बिजली कटौती के खिलाफ आंदोलन करने को मजबूर हैं।

बघेल और सिंहदेव के बयान कांग्रेस के सनातन विरोधी होने का प्रमाण

मुगलों के काल में हिन्दू दमन का कोई इतिहास में उदाहरण नहीं

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता नलिनीश ठोकने ने सनातन विरोधी बयानों के लिए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव पर पलटवार करते हुए कहा, बघेल, जिनके डीएनए में रामद्रोह रचा-बसा है, और सिंहदेव जो कभी कांग्रेस की राजनीति में एक-दूसरे के धुर विरोधी हुआ करते थे, आज एक सुर में सनातन संस्कृति के खिलाफ बोल रहे हैं। इससे यह आईने की तरह साफ है कि दोनों कांग्रेसी नेता कांग्रेस की सोची समझी रणनीति के तहत लिखी हुई सनातन विरोधी संक्रष्ट पढ़ रहे हैं। श्री ठोकने ने कहा, बघेल और सिंहदेव के बयान कांग्रेस के सनातन-विरोधी होने का प्रमाण है। उनके ये बयान सिख पंथ के अनुयायियों का भी घोर अपमान है। एक ओर जब देश में वीर बाल दिवस मनाकर सिख पंथ के दशम गुरु गोबिन्द सिंह साहेब के चारों साहिबजादों के अमर बलिदान को नमन कर रहा है, तब कांग्रेस के नेताओं को नौ वर्ष के जोरावर सिंह और छह वर्ष के फतेहसिंह को मुगल आक्रांताओं द्वारा जिन्दा चुनवा दिया जाना, इन साहिबजादों व उनकी माता गूजरी को गर्म दूध देने वाले बाबा मोतीराम मेहरा और उनके परिवार को कोल्हू में पीसकर शहीद कर दिया जाना नजर नहीं आ रहा है और बड़ी निर्लज्जता के साथ कांग्रेसी यह कह रहे हैं कि मुगलों के काल में हिन्दू दमन का कोई इतिहास में उदाहरण में नहीं है। कांग्रेस नेता बताएं कि जम्मू-कश्मीर की डेमोग्राफी 12वीं सदी से पहले क्या थी और 12वीं सदी के बाद क्या है। मुगल कांग्रेस के शहंशाह बघेल और उनके सिपहसालार सिंहदेव को वामपंथी चश्मा उतारकर देश का वास्तविक इतिहास पढ़ने की जरूरत है।

हिंदूवादी संगठन से जुड़े कार्यकर्ता पुलिस को चकमा देकर तेलीबांधा थाना पहुंचे

सैकड़ों की संख्या में गिरफ्तारी देने पहुंचे बजरंग दल-विहिप कार्यकर्ता ने थाना घेरा

रायपुर। मैग्नेटो मॉल में तोड़फोड़ करने के आरोप में सात बजरंग दल कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी के विरोध में बजरंग दल तथा विश्व हिंदू परिषद के ने शनिवार को तेलीबांधा थाने का घेराव कर कार्यकर्ताओं कार्यकर्ताओं ने सिविल लाइंस थाना घेराव करने दी थी चेतावनी प्रदर्शन किया। हिंदूवादी संगठन से जुड़े कार्यकर्ताओं ने सिविल लाइंस थाने का घेराव करने की चेतावनी दी थी। मोतीबाग के पास एकत्रित होने के बाद कार्यकर्ता सिविल लाइंस थाने का घेराव करने के बजाय पुलिस को चकमा देकर तेलीबांधा पहुंच गए और वहां जमकर प्रदर्शन करने के साथ चक्काजाम किया। उल्लेखनीय है कि कांकेर, आमाबेड़ा में धार्मिक विवाद के बाद हुई हिंसा के विरोध में सर्वसमाज ने बुधवार को प्रदेश बंद का आव्हान किया था। बंद के दौरान प्रदर्शनकारियों ने मैग्नेटो मॉल में क्रिसमस की तैयारी में बनाए जा रहे सेट में जमकर तोड़फोड़ करते हुए लोगों के साथ बदसलूकी की। मॉल प्रबंधन की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात 30 से 40 लोगों के खिलाफ बलवा, तोड़फोड़ सहित कई अन्य गंभीर धाराओं में अपराध दर्ज किया था। अपराध दर्ज होने के बाद पुलिस ने सीसीटीवी तथा लोगों द्वारा शूट किए गए वीडियो के आधार पर तोड़फोड़ करने वालों की पहचान कर सात प्रदर्शनकारियों को शुक्रवार को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर जेल दाखिल किया। इसी के विरोध में हिंदूवादी संगठन से जुड़े लोगों ने प्रदर्शन किया।

धमकी को देखते हुए सिविल लाइंस में की गई थी तैयारी

हिंदूवादी संगठन से जुड़े नेताओं ने पुलिस प्रशासन को लिखित में सिविल लाइंस थाने का घेराव करने की चेतावनी दी थी। चेतावनी को देखते हुए पुलिस ने सुरक्षा के लिहाज से सिविल लाइंस थाने में बैरिकेडिंग करने के साथ फोर्स की तैनाती की थी। दूसरी ओर हिंदूवादी संगठन से जुड़े कार्यकर्ता मोतीबाग के पास एकत्रित हुए और वहां से सिविल लाइंस जाने के बजाय सीधा तेलीबांधा थाना पहुंच गए। तेलीबांधा थाना में घेराव को लेकर पुलिस ने पूर्व में किसी तरह से तैयारी नहीं की थी, इसलिए वहां अफरा-तफरी की स्थिति निर्मित हो गई। सिविल लाइंस थाना की सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों को आनन-फानन में तेलीबांधा शिफ्ट किया गया।

राजा राव पठार के वीर मेला में दूर-दूर से दर्शनार्थी आते हैं

अरमान खान अश्क

छत्तीसगढ़ के प्रमुख जीवनदायिनी महानदी से खारुन नदी के मध्य आदिकाल से विशाल पर्वत श्रृंखला विद्यमान हैं। बालोद एवं कांकेर जिले को जोड़ने वाली इस पर्वत श्रृंखला को राजा राव पठार के नाम से जाना जाता है। यह संपूर्ण इलाका दंडकारण्य भी कहलाता है, जहां पर्वत श्रृंखला में नदी, नाले, पहाड़, झरने और वनों से आच्छादित रमणीक स्थान होने के कारण यह संपूर्ण क्षेत्र पर्यटन के साथ साथ पिकनिक स्थल भी है। पहाड़ के मध्य भाग के सबसे ऊंचे स्थान के पठार में स्थित है। 52 गांवों के देवी देवताओं के राजा' राजा राव देव स्थल' यह पवित्र स्थल धमतरी कांकेर राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 30 के निकट ही है। किंवदंती है कि इस पवित्र स्थल में बरसों से गणेश चतुर्थी के दिन धान की बालियां अर्पित की जाती है जिसे बाल पर्व के नाम से जाना जाता है। दिसम्बर माह में तीन दिवसीय विशाल मेले का आयोजन यहां किया जाता है। मेले में आसपास के देवी देवताओं को विधिवत आमंत्रित किया जाता है। इस

विशाल मेले में जिसमें छत्तीसगढ़ सहित आंध्र प्रदेश, ओडिशा, महाराष्ट्र व अन्य राज्यों से आदिवासी समाज के हजारों श्रद्धालु इस वीर मेला में एकत्र होते हैं। इस मेले में भक्तों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है।

छेरछेरा तिहार में दान का महत्व

डा. रमाकांत सोनी

प्रत्येक वर्ष पौष पूर्णिमा को सूरज निकलने से दिन ढलने तक मनाया जाने वाला यह त्योहार छेरछेरा वर्ष भर के कड़े परिश्रम के बाद फसल के खलिहान से होते हुए कोठी में पहुंचने का त्योहार है। यह बच्चों के मासूम उल्लास, अन्नदान की महिमा और आस्था का त्योहार है। इसीलिए बच्चे छेरछेरा... कोठी के धान ल हेरते हेरा के घोष में कोठी के भरे रहने, कृषक के चहुमुखी विकास तथा उसके घर के अन्न और धन धान्य से भरे रहने की शुभकामना होती है। जीवन को साथ साथ जीने की मंगल कामना जीवन को भरपूर जीने की चाह, समृद्धि, सामथ्य, संपन्नता, समग्रता, सुख-आमोद प्रमोद और विस्तार तथा जीवन के अनंत आयाम जो भविष्य में आने वाले हैं उस आनंद की कामना की जाती है। साथ ही यह पर्व पौरुष और सामर्थ्य से अर्जित फसल को अन्नदान महाकल्याण के भाव से दानी होने के अहंकार से शून्य होकर दान देने का भी महापर्व है। यह दिवस उन किशोरों का भी है जो मांदर, झांझ, मंजीरा और डंडा लेकर सामूहिक नृत्य में सम्मिलित होकर थिरकने लगता है और किसान यहां भी अपने बिरादरी से नवयुवकों के नर्तक दल को सम्मानित करता है। सुआ नृत्य का आकर्षण भी इस दिन देखने को मिलता है।

कभी नहीं सूखता रामझरना का पानी

कमलेश यादव

छत्तीसगढ़ में रामायणकालीन साक्ष्य अभी भी देखे जा सकते हैं। इनसे संबंधित अनेक जनश्रुति भी प्रचलित हैं। इसी तरह रामायणकालीन साक्ष्य रायगढ़ के समीप भूपदेवपुर स्टेशन के पास स्थित है। यहां पर राम झरना में पहाड़ों की ऊंचाई से झर झर ध्वनि से पर्यटकों का मन आनंदित हो जाता है। मान्यता है कि भगवान राम इस झरने में स्नान किए थे, इस कारण इस झरने का नाम राम झरना रखा गया। इस झरने में चमत्कारिक रूप से भीषण गर्मी में भी पानी कभी नहीं सूखता। जबकि आसपास के ऐसे स्थल पूरी तरह से सूखे रहते हैं। इस सौंदर्यपूर्ण स्थल को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है।

अंचल में प्राकृतिक व प्रस्तर निर्मित गुफाएं

डा. टी. आर. रामटेके

प्रागैतिहासिक काल से ही मानव ने अपने निवास के लिए नैसर्गिक शैलाश्रय या पहाड़ों को काट कर गुफाओं का निर्माण किया था। कुछ गुफाएं प्राकृतिक थी, लेकिन आदिम मानव ने पहाड़ की चट्टान को सावधानी से अपने प्रारंभिक हथियार पत्थर की कुल्हाड़ी व छेनी से काट कर उसे अपने निवास योग्य बनाया था।

प्राचीन भारतीय वास्तु कला में मानव सभ्यता की सर्वप्रथम स्थापत्य कला है। प्रागैतिहासिक काल से ही मानव ने अपने निवास के लिए नैसर्गिक शैलाश्रय या पहाड़ों को काट कर गुफाओं का निर्माण किया था। कुछ गुफाएं प्राकृतिक थी, लेकिन आदिम मानव ने पहाड़ की चट्टान को सावधानी से अपने प्रारंभिक हथियार पत्थर की कुल्हाड़ी व छेनी से काट कर उसे अपने निवास योग्य बनाया था। सामान्य गुफा के भीतर एक गर्भ गृह और सामने छोटे स्तंभों पर आश्रित मंडप होता था। गुफाओं के सामने छोटे बरामदे बना दिए जाते थे, जो खंभों पर आधारित रहते थे। बड़ी गुफाएं दो मंजिल होती थी, जिनमें ऊपर का खंड नीचे की अपेक्षा कुछ पीछे हटा कर बनाया जाता था, जिसमें उसके सामने के मंडप के तीन ओर एक या डेढ़ फुट ऊंची एक आसन पिंडिका बनी होती थी। गुफाओं में प्रवेश द्वार होते थे। गर्भशालाओं को एक दूसरे से अलग करने के लिए तीन फुट ऊंची भित्तियां बनाई जाती थी, जो चट्टानों में ही उकेरी जाती थी। इस प्रकार की गुफाएं मध्य भारत में बहुतायत से पाई गई हैं। छत्तीसगढ़ में आदिम मानव निर्मित गुफाएं राजनांदगांव जिला में अंबागढ़ चौकी, दर्रेकसा, बालोद जिले में चितवा डोंगरी, रायगढ़ जिले में कबरा पहाड़, सिंघनपुर, ऑगना, सरगुजा जिले में सीताबेंगरा व जोगीमारा, जगदलपुर जिले में तीरथगढ़, महासमुंद जिले में मोहदीगढ़, एवं छेरी गोदरी गुफा है।

बस्तर अंचल में कानयांग पूजन

डा. किरण नुरूटी

बस्तर अंचल में खूबसूरत और आकर्षक कन्याओं को कानयांग कहा जाता है। वे लोगों को लाभ देना चाहती हैं। पर इन्हें भी पर्याप्त प्रेम और ध्यान की आवश्यकता होती है। यह जल और जंगल की देवियां भी होती हैं। एक कन्या सल्फी के पेड़ में रहती हैं, दूसरा बिजली के रूप में आकाश में चमकती हैं। मुरिया लोग जब मछली पकड़ने जाते हैं तब इनकी पूजा करते हैं। मछली पकड़ने के पूर्व उन्हें भेंट का वादा करते हैं और अगर पर्याप्त मात्रा में मछली मिल जाए तो जल देवी का सम्मान करते हैं। विवाह हेतु कन्या एवं वर को नदी पार जाना होता है तो उन्हें गोद में उठा कर पार कराया जाता है, तथा नदी पार करते समय जल कन्याओं को भेंट करने के लिए दो अंगूठियां पानी में फेंकी जाती हैं।

वैवाहिक रस्म में भी हल्दी लगे मौर को जल में प्रवाहित की जाती है। जब ढोल बनाने के लिए चमड़ा नदी में भिगोते हैं तब पानी दूषित होने पर नाराज न हो इसलिए येर कानयांग को उपहार चढ़ाए जाते हैं। येर कानयांग के अन्य नाम कानयांग और बिसरत कानयांग हैं। येर कानयांग थोड़ी संवेदनशील होती हैं और कभी कभी पुरुषों पर मगरमच्छ के रूप में आक्रमण कर देती हैं। अगर ऐसा हो जाए तो गांव वाले उन्हें महंगे उपहार भेंट करते हैं जैसे एक सुअर, आंवला के सात छल्ले, सिर में लगाने के लिए सिंदूर और कलाइयों के लिए चूड़ियां।

गम और खुशियों भरा रहा साल

कई उपलब्धियों और चुनौतियों के साथ साल 2025 भी अपने अंतिम दिनों में पहुंच गया है। अब जब हम उम्मीदों भरी निगाह से साल 2026 का स्वागत करने के लिए उत्सुक हैं, तो हमें इस बीत रहे साल के विवादों और मुद्दों पर भी एक नजर डालनी तो बनती है, जिन्होंने देश में खूब हंगामा मचाया और जनमानस के मन-मस्तिष्क को जमकर झकझोरा। वहीं कई उपलब्धियों ने भी इस साल को यादगार बनाया।

ऑपरेशन सिंदूर

22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में एक ऐसा आतंकी हमला हुआ, जहां लोगों का धर्म पूछकर उन्हें बर्बरता से मारा गया। जम्मू कश्मीर ने आतंकवाद का लंबा दौर देखा है, लेकिन वहां आमतौर पर पर्यटकों को निशाना नहीं बनाया जाता था। लेकिन पहलगाम के आतंकी हमले में निर्दोष नागरिकों को जिस बेरहमी से मारा गया, उसने हर भारतीय को गुस्से और गम से भर दिया। इस हमले में 26 लोगों की जान चली गई। यह साफ तौर पर देश में सांप्रदायिक हिंसा भड़काने और देश को हिंसा की आग में धकेलने की साजिश थी, लेकिन भारत के नागरिकों ने दिखा दिया कि देश में भाईचारे की जड़ें इतनी कमजोर नहीं हैं कि ऐसी साजिशें सफल हो जाएं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने जवाबी कार्रवाई की और ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया और कई खूंखार आतंकियों को उनके घर में घुसकर मारा। भारत की प्रतिक्रिया लक्ष्य केंद्रित, नपी तुली थी और इसमें पाकिस्तान के आम नागरिकों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया। हालांकि पाकिस्तान ने इसे अपनी संप्रभुता पर हमला माना और भारत पर उकसावे की कार्रवाई के तहत हमले किए। इसके बाद भारत ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया। चार दिन चले इस संघर्ष में भारत के हमलों का पाकिस्तान के पास कोई जवाब नहीं था और आखिरकार उसने संघर्ष विराम की पेशकश की, जिसे भारत ने स्वीकार कर लिया।

मोदी-ट्रंप के रिश्ते और टैरिफ युद्ध

ये साल भारत-अमेरिका के संबंधों में आई खटास के लिए भी याद किया जाएगा। इससे पहले भारत और अमेरिका के संबंध लगातार मजूबत हो रहे थे। जॉर्ज डब्ल्यू बुश के कार्यकाल में भारत और अमेरिका के बीच हुए नागरिक परमाणु समझौते से भारत-अमेरिकी संबंधों का नया अध्याय शुरू हुआ था। फिर चाहे बराक ओबामा का कार्यकाल हो या फिर जो बाइडन का भारत-अमेरिकी संबंधों में लगातार बेहतरी देखी गई, लेकिन इस साल अपने दूसरे कार्यकाल में डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता में आने के बाद से भारत और अमेरिका के संबंधों में थोड़ी खटास आई है। पहले तो ट्रंप ने भारत पर सबसे ज्यादा टैरिफ वसूलने का आरोप लगाकर भारत पर भारी-भरकम टैरिफ लगाए। इसके बाद ऑपरेशन सिंदूर में भी ट्रंप ने पाकिस्तान को शह दी और पाकिस्तानी जनरल की पीठ थपथपाई। इसके बाद रूस से तेल खरीदने और यूक्रेन युद्ध को वित्तपोषित करने का आरोप लगाकर ट्रंप ने फिर से भारत पर टैरिफ लगा दिया। इस तरह अमेरिका ने भारत पर 50 फीसदी टैरिफ लगाया, जो दुनिया के देशों पर लगाए गए सबसे ज्यादा टैरिफ में से एक है। अब भारत के पास संयम बरतने के अलावा फिलहाल बहुत ज्यादा विकल्प नहीं हैं। ट्रंप की जैसी शख्सियत है कि वे कब क्या कर दें, उसे देखते हुए हम कह सकते हैं कि भारत-अमेरिकी संबंध बहुत अच्छी स्थिति में नहीं हैं।

एसआईआर पर हंगामा

बिहार विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले चुनाव आयोग ने वहां मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) करने का एलान किया। इसे लेकर देशभर में खूब हंगामा हुआ और विपक्ष ने इस पर कई कानूनी और वैधानिक सवाल भी उठाए। विपक्ष ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता को कटघरे में खड़ा किया और चुनाव आयोग पर सरकार के इशारे पर काम करने का आरोप लगाया। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर वोट चोरी करने का आरोप लगाया। हालांकि चुनाव आयोग और सरकार ने विपक्ष के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया और विपक्ष पर घुसपैठियों को शह देने का आरोप लगाया। बिहार में एसआईआर के तहत 65 लाख नाम हटाए गए। इसके बाद देश के 12 राज्यों में भी एसआईआर प्रक्रिया चल रही है, जिसमें ड्राफ्ट में करीब साढ़े तीन करोड़ नाम कट चुके हैं। चुनाव आयोग की तैयारी पूरे देश में एसआईआर कराने की है।

अहमदाबाद प्लेन हादसा

अहमदाबाद में 12 जून को एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीमलाइनर विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे में 241 लोगों की मौत हुई, जबकि एक व्यक्ति जीवित बचा। मृतकों में 169 भारतीय, 52 ब्रिटिश, 7 पुर्तगाली और एक कनाडाई नागरिक शामिल थे। विमान जिस हॉस्टल इमारत से टकराया, वहां से 29 शव बरामद हुए।

वक्फ विधेयक पर गरमाया माहौल

इस साल वक्फ कानून, 1995 में सरकार ने कुछ बदलाव करते हुए वक्फ संशोधन विधेयक पेश किया, जिसे लेकर देश में खूब विवाद हुआ। इस बदलाव के विरोध में देश में मुस्लिम संगठनों ने कड़ी नाराजगी जताई और कई जगह इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी हुए। संशोधन के तहत वक्फ कानून में कलेक्टर को वक्फ संपत्तियों के सर्वेक्षण और स्वामित्व का निर्धारण करने का अधिकार दिया गया। साथ ही वक्फ बोर्ड में महिलाओं और गैर मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति का भी प्रावधान किया गया।

नई जीएसटी दरें लागू

नई जीएसटी दरें 22 सितंबर 2025 से लागू हुई। अब दो मुख्य टैक्स स्लैब है-5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत। आवश्यक वस्तुओं पर 5 प्रतिशत जीएसटी लागू किया गया, जबकि लग्जरी सेवाओं पर 40 प्रतिशत तक टैक्स लगाया गया।

महाकुंभ का भव्य आयोजन

13 जनवरी से 26 फरवरी तक चला यह विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन रहा, जिसमें 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालु संगम में स्नान के लिए आए। शाही स्नान, सांस्कृतिक कार्यक्रम और डिजिटल व्यवस्था की सराहना हुई। प्रधानमंत्री मोदी समेत कई वैश्विक हस्तियां शामिल हुई।

आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप जीता

भारतीय टीम ने पहली बार आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप का खिताब जीता। 52 वर्षों में पहली बार भारतीय टीम यह उपलब्धि हासिल करने में सफल रही। हरमनप्रीत कौर के नेतृत्व में भारत ने 2 नवंबर 2025 को नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में साउथ अफ्रीका को 52 रन से हराकर खिताब अपने नाम किया।

तैयार हैं हम... हो सकती है ये बड़ी 7 घटनाएं

अधिकतर ज्योतिषियों को मानना है कि ग्रह नक्षत्रों के अनुसार वर्ष 2025 से ज्यादा खतरनाक सिद्ध होने वाला है अगला वर्ष 2026, क्योंकि इस दौरान बृहस्पति और मंगल की चाल बदलेगी। हालांकि शनि फिलहाल वक्री हैं। इसी के साथ ही यदि हम हिंदू संवत्सर की बात करें तो फिलहाल सिद्धार्थ संवत्सर चल रहा है इसके बाद 19 मार्च 2026 से रौद्र नामक संवत्सर प्रारंभ होगा। आओ जानते हैं कि ग्रह नक्षत्रों के आधार पर कैसा रहेगा वर्ष 2026 और क्या हो सकती है बड़ी घटनाएं।

1. **भारत की राजनीति में बड़े बदलाव की संभावना है।**
2. **भारत में आतंकवादी हमला होने की संभावना प्रबल है।**
3. **पंजाब, बंगाल, कश्मीर, ओड़िसा और पूर्वोत्तर राज्य में समस्या उत्पन्न हो सकती है।**
4. **भारत में बड़ा आंदोलन हो सकता है जो भारत की राजनीति को अस्थिर करेगा।**
5. **किसी घटना-दुर्घटना में एक साथ सैंकड़ों लोगों की मौत की संभावना है।**
6. **भारत की सीमाओं पर तनाव बढ़ जाएगा।**
7. **भारत में प्रदूषण अपने चरम पर होगा, मौसम और हवाओं से लोग परेशान रहेंगे। प्राकृतिक आपदाएं बढ़ जाएगी।**

ग्रह गोचर

वर्ष 2026 में बृहस्पति 2 जून तक मिथुन राशि में रहेंगे, फिर 2 जून से 31 अक्टूबर तक कर्क राशि में रहेंगे। कुंभ से निकलकर 5 दिसंबर को राहु मकर में गोचर करेगा। सिंह से निकलकर केतु कर्क में गोचर करेगा। 16 जनवरी 2026 को धनु से निकलकर मंगल मकर में गोचर करेगा। इसके बाद वह कुंभ, मीन, मेष, मिथुन, कर्क और सिंह में गोचर करेंगे।

ग्रह गोचर का परिणाम

गुरु की मिथुन राशि में स्थिति के दौरान, मीडिया में भ्रम, झूठी सूचनाओं का प्रसार और कूटनीतिक तनाव बढ़ सकते हैं। दो देशों के बीच तनाव चरम पर रहेगा। कर्क राशि में गुरु के उच्च अवस्था में आने पर, राष्ट्रीयता की भावना, सांस्कृतिक पहचान और नए वैश्विक गठबंधन उभर सकते हैं। गुरु की कर्क राशि में उच्च अवस्था के दौरान, जलवायु परिवर्तन के कारण बाढ़, तूफान और जल संबंधित प्राकृतिक आपदाएँ बढ़ सकती हैं। जब गुरु कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, तो यह उच्च अवस्था में होंगे, जिससे कुछ समय के लिए आर्थिक स्थिरता, सरकारी कल्याण योजनाओं, कृषि और रियल एस्टेट क्षेत्र में सुधार की उम्मीद की जा सकती है। 2 जून 2026 मंगलवार को मध्यरात्रि 02:25 पर जब बृहस्पति कर्क राशि में गोचर करेंगे तो फिर से भारत पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर रह सकता है। हालांकि भारत पर इसका कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। 31 अक्टूबर 2026 में गुरु सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे प्रभावशाली नेताओं का उदय और वैश्विक राजनीति में बदलाव की संभावना है। भारत की भूमि, नभ और जल में शक्ति बढ़ेगी लेकिन उसके शत्रु भी साजिश रचना में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे।

मंगल

16 जनवरी 2026 को धनु से निकलकर मंगल मकर में गोचर करेगा। इसके बाद वह कुंभ, मीन, मेष, मिथुन, कर्क और सिंह में गोचर करेंगे। इस गोचर के चलते भारत के खिलाफ कोई भी शक्ति सफल नहीं हो पाएगी। वर्ष 2026 में भारत एक बड़े युद्ध में जा सकता है। यदि ऐसा होता है तो 28 दिसंबर 2027 तक यह युद्ध चल सकता है। वर्ष 2026 में एक ओर जहां सीमाओं पर संघर्ष बढ़ेगा वहीं प्रकृतिक आपदा, भूकंप और खद्यान संकट से दुनिया परेशान रहेगी।

12 जुलाई से 15 अगस्त के बीच का समय भयंकर रहने वाला है जबकि गुरु, चंद्र और सूर्य यानी यह तीनों ग्रह कर्क राशि में होंगे। यानी 15 से 12 अगस्त के बीच यह इसी राशि में रहेंगे। इस युति के बाद भारत के लिहाज से स्थितियों में सुधार होगा लेकिन विनाश के बाद। गुरु, चंद्र और सुर्य तीनों ग्रहों का पुष्य नक्षत्र में जा रहे हैं जोकि शनि का नक्षत्र है। यह शनि का नक्षत्र है। शनि और पुष्य दोनों ही न्याय के ग्रह नक्षत्र हैं जो तीनों ग्रहों के साथ जुडकर अलग-अलग कहानी लिखने का काम करेंगे। सूर्य के साथ आग और चंद्र के साथ जल प्रलय की उत्पत्ति करेंगे। यह विध्वंस के बाद सृजन की नींव भी रखेंगे। यह मीन राशि का शनि जुलाई और अगस्त 2026 के माह में अपनी पूर्ण विनाश लिया का सृजन करेगा। ऐसा ग्रह योग संकेत देते हैं। अधिकतर ज्योतिषियों का मानना है कि वर्ष 2020 से देश और दुनिया का भविष्य बदलने लगा है जब शनि ने मकर में प्रवेश किया था। मकर से लेकर मेष तक यानि 2029 तक शनि की यह गति देश और दुनिया का भूगोल ही नहीं भविष्य और मौसम भी बदल कर रख देगी। यानि विश्व के बदलने की शुरुआत 2020 से हो चुकी है 2025 इसका टर्निंग पाइंट है और अब 2026 में होगा महायुद्ध। हालांकि कुछ ज्योतिषियों का मानना है कि शनि के मेष में जाने पर आएगा विश्व में महासंकट। शनि वर्ष 2028 में मेष में प्रवेश करेगा।

रौद्र संवत्सर का परिणाम

वर्तमान में विक्रम संवत 2082 के अंतर्गत कालयुक्त सिद्धार्थ संवत्सर चल रहा है। इस संवत्सर के फलानुसार भारत में और दुनिया में युद्ध और आतंकवाद की घटनाओं के दर्शन होंगे, जो एक बड़े युद्ध की भूमिका तय करेंगे। महंगाई बढ़ेगी। वर्षा खंडित होगी। कई जगह अकाल और कई जगह बाढ़ के हालात देखने को मिलेंगे। वैश्विक स्तर पर दोस्त और दुश्मन तय हो जाएंगे। सिद्धार्थ संवत्सर के बाद विक्रम संवत 2083 जब प्रारंभ होगा तब शुरू होगा रौद्र नाम संवत्सर प्रारंभ होगा। 19 मार्च 2026 से रौद्र नाम संवत्सर प्रारंभ होगा। यानी विक्रम संवत 2083 से प्रारंभ होगा रौद्र संवत्सर। यह देश और दुनिया में नरसंहार लेकर आएगा। मध्य एशिया में नरसंहार जारी है और अब यह दक्षिण एशिया में भी देखा जाएगा। इस दौरान मौसम में भारी बदलाव होगा और किसी बड़े भूकंप के आने या ज्वालामुखी फटने के संकेत भी मिलते हैं।

साल 2026 में ग्रहों का बेहद शुभ योग, कुंभ सहित पांच राशियों के लिए भाग्यशाली रहेगा यह साल

साल 2026 एक बदलाव के साल होने वाला है। दरअसल, इस साल ग्रहों का ऐसा संयोग बना हुआ है जो कुछ राशियों के लिए भाग्यशाली रहने वाला है। साल 2026 में गुरु, राहु और केतु जैसे बड़े ग्रह गोचर करने जा रहे हैं। इस साल 2 जून को गुरु कर्क राशि में पहुंच जाएंगे इसके बाद अतिचारी चाल से चलते हुए गुरु अक्टूबर में सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। वहीं, 25 नवंबर को राहु और केतु गोचर करेंगे। जहां राहु कुंभ राशि से मकर राशि में प्रवेश करेंगे वहीं, केतु का गोचर कर्क राशि में होगा। साथ ही सालभर शनि वक्री मार्गी होकर चलेंगे। जोकि कई राशियों के जीवन में बड़े उतार चढ़ाव लेकर आएंगे। लेकिन, यह गोचर करीब 5 राशियों के लिए विशेष रुप से भाग्यशाली रहने वाला है।

कुंभ

कुंभ राशि के लोगों के लिए साल 2026 भाग्यशाली रहने वाला है। क्योंकि, राहु आपके प्रथम भाव में गोचर करेंगे। ऐसे में आपके अंदर एक अलग ही जुनून देखने को मिलेगा साथ ही आपके अंदर रचनात्मकता देखने को मिलेगी। आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल रहेंगे। साथ ही आपको इस वर्ष आपको कई ऐसे अवसर मिलेंगे जो आपको भरपूर लाभ दिलाएंगे। इस साल आपकी आय में तेजी से वृद्धि देखने को मिलेगी। आपको सलाह है कि निवेश करेंगे तो आपको अनावश्यक खर्च से राहत मिलेगी। पिछले दो वर्षों में आपने अपने भीतर कई पुराने पैटर्न, कमजोरियों और अनचाही भावनाओं को छोड़ा है। अब ब्रह्मांड आपको एक नई दिशा, नया जीवन-खाका दे रहा है।

वृषभ

साल 2026 वृषभ राशि के लोगों के लिए काफी शुभ रहने वाला है। इस साल की शुरुआत काफी धमाकेदार होगी। यह साल आपके लिए सौभाग्य के साथ-साथ स्थिरता और अच्छी सेहत लेकर आने वाला है। इस साल आपको आर्थिक लाभ मिलेगा जो आपने पिछले काफी समय से निर्णय लिए थे उनका फल अब आपको मिलना शुरू होगा। इस साल अगर आप कोई नया व्यापार शुरू करते हैं तो आपको इस साल उसमें सफलता मिल सकती है। व्यापार में निवेश करना आपके लिए सुनहरे अवसर लेकर आएगा। 2 जून से 31 अक्टूबर तक आपको सुनिश्चित लाभ मिलेगा। इस साल, अपने परिवार और दोस्तों के साथ अपने रिश्ते को बेहतर करें। अपनी उपलब्धियों का जश्न उनके साथ मनाएं।

मिथुन

मिथुन राशि के लोगों के लिए साल 2026 अच्छा रहने वाला है। इस साल की शुरुआत में आप सभी बाधाओं को आसानी से पार कर लेंगे। यह साल आपको ऊंचाइयों पर ले जाने का समय है। यह समय आपके चमकने का है। आप इस समय बहुत ही बुद्धिमानी से निर्णय लेंगे। आपकी वाणी इस दौरान पहले से काफी प्रभावशाली रहेगी। बात करें आपके करियर की तो आपके करियर में काफी तेजी आएगी। बात करें आपके स्वास्थ्य की तो इस साल आपकी स्वास्थ्य संबंधी समस्या दूर हो सकती है। आपको इस साल पारिवारिक विरासत के माध्यम से धन प्राप्त हो सकता है। इस राशि के अविवाहित जातकों के विवाह के योग बन सकते हैं। आपको एक आदर्श जीवनसाथी मिल सकता है।

कर्क

साल 2026 में इस राशि गुरु का गोचर आपकी राशि में होगा। ऐसे में कर्क राशि के लोगों के लिए साल 2026 ज्ञान और परिवर्तन लेकर आएगा। इस वर्ष के समाप्त होने तक आप अपने ज्ञान से काफी कुछ हासिल कर सकते हैं। इस साल आपके अंदर एक अलग ही आत्मविश्वास और ज्ञान का विस्तार होगा। इस साल आपका अंदर काफी विकास देखने को मिलेगा। आप पहले से काफी मजबूत और स्वतंत्र बनकर उभरेंगे। इस साल आपकी आर्थिक स्थिति पहले से काफी अच्छी रहेगी। हालांकि, कानूनी मुद्दों से संबंधित मामलों में कुछ बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं। साथ ही यह साल आपको सिखाएंगा की हर सुख सिर्फ भौतिक सुख संपत्ति का नहीं होता है। आप इस अवधि में काफी मजबूत बनकर उभरेंगे।

मकर

मकर राशि के लोगों के लिए वर्ष 2026 आर्थिक रूप से बदलाव लेकर आने वाला है। आपकी आर्थिक स्थिति इस साल लाभकारी रहेगी। इस अवधि में आप अपने मेहनत से आगे बढ़ेंगे। आप जो भी मेहनत करेंगे उसका फल आपको मिलेगा। इस अवधि में आप आर्थिक लाभ और सफलता आसानी से हासिल कर लेंगे। हालांकि, इस वर्ष आपके कुछ खर्चे रह सकते हैं लेकिन, व्यापारियों के लिए समय काफी लाभकारी रहने वाला है। क्योंकि, आप वैश्विक स्तर पर अपने बिजनेस का विस्तार कर सकते हैं। इस साल आपकी भौतिक इच्छाओं में काफी वृद्धि देखने के मिलेगी। सावधानीपूर्वक योजना बनानी चाहिए। आपके लिए सलाह है कि इस साल अपने सेविंग्स पर थोड़ा ज्यादा फोकस करें।

गरीबों की जेब में डाका ?

मोर आवास बनाने के लिए 187 करोड़ रुपए ज्यादा वसूले

- **मकान भी दूसरों को दे दिए गए, योजना का उद्देश्य विफल**
- **कैग की रिपोर्ट से सामने आई आर्थिक अनियमितता, गड़बड़ी**

छत्तीसगढ़ में गरीबों की थाली में कटौती होने की खबरें आती थीं। अब तो उन्हीं गरीबों की जेबों में भी मुनाफाखोरों और अफसरशाही की वजह से डाका पड़ गया है। अपने खुद के आशियाने की उम्मीदों को लिए बैठे गरीब-मुफ़लिस जमा पूंजी तक लुटा दिए लेकिन उन्हें मोर आवास योजना का लाभ नहीं मिला। ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सुशासन के लिए कोई कोताही बारात रहे हैं। जनहित और प्रदेश के अंतिम व्यक्ति तक सुशासन की योजना का लाभ पहुंचाने वाले आला ओहदेदार तो कवायद कर रहे हैं लेकिन मंझोले और मातहत अधिकारी अपनी लालसा के चक्कर में मोर आवास योजना के क्रियान्वयन को पलीता लगा रहे हैं।

प्रमुख संवाददाता/विकास यादव
मोबाईल नंबर 9425528000

शहर सत्ता/रायपुर। पीएम आवास योजना के एक घटक मोर मकान मोर आवास योजना के क्रियान्वयन में एक बड़ी गड़बड़ी सीएजी ने पकड़ी है। हुआ ये है कि हितग्राहियों से उनके हिस्से के अंशदान से अधिक 187 करोड़ रुपयों से अधिक की राशि क्सूल ली गई है। खास बात ये है कि जो राशि सरकार को राज्यांश के रूप में देनी थी, वह राशि हितग्राहियों से वसूल ली गई। यह योजना फरवरी 2022 से शुरू हुई थी। इस दौरान राज्य में कांग्रेस सरकार थी। उसके बाद भी वसूली की राशि नहीं लौटाई गई। सीएजी ने इसे गलत माना है।

गरीबों के लिए बनी योजना अलग

प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी योजना के दिशानिर्देश के अनुसार, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग परिवारों को खबर लाख रुपए तक की वार्षिक आय वाले परिवारों के रूप में परिभाषित किया गया है। भागीदारी में किफायती आवास घटक के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हितग्राहियों को 150 लाख केंद्रीय सहायता तथा 2.50 लाख रुपए की राज्य सहायता प्रदान करके लाम प्रदान करता है और हितवाही को प्रत्येक आवासीय इकाईयों के लिए केवल 75 हजार रुपर लाख का अंशदान देना तय था।

गरीबों की जगह दूसरों को मिला फायदा

सीएजी की लेखापरीक्षा में पाया गया कि स्लम निवासियों के लिए भागीदारी में किफायती आवास के तहत स्वीकृत आवासीय इकाईयों का आवंटन गैर स्लम निवासियों को लाम देने के लिए बुनियादी पात्रता मानदंडों को संशोधित करते गैर मकान मोर आस के तहत आवंटित किया गया था। इस प्रकार, स्लम विवासियों को स्थानांतरित करने की योजना का मुख्य उद्देश्य विफल हो गया क्योंकि सलम निवासियों के लिए जागीदारी में किफायती आवास के तहत स्वीकृत आवासीय इकाईयों का 50 प्रतिशत ठगैर स्लम निवासियों को व्यप्वर्तित या आवंटित किया गया था। इसके अलावा, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत प्रदान की गई केंद्रीय सहायता का लाभ इच्छित हितग्राहियों तक नहीं पहुंचा, क्योंकि भागीदारी में किफायती आवास की योजना आरम्भ में राज्य सरकार द्वारा केवल स्लम निवासियों के लिए बनाई गई थी।

कैग की रिपोर्ट में हुआ राजफ़ाश

मोर मकान मोर आस दिशानिर्देशों की आगे की जांच से सीएजी को पता चला कि प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी के अनुसार मानक 75 हजार रुपए हितग्राही अंशदान के स्थान पर हितग्राहियों को प्रति आवासीय इकाईयों 3 लाख 25 हजार (राज्य के हिस्से के ढाई लाख सहित) का भुगतान करना आवश्यक था। हालांकि, आवासीय इकाईयों की लागत 2.98 लाख से 3.87 लाख रुपए के बीच थी। इसके अतिरिक्त, योजना के दिशा निर्देश राज्य स्तरीय स्वीकृति और निगरानी समिति को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत नहीं किए गए थे, और न ही केंद्रीय स्वीकृति और निगरानी समिति से अनुमोदन प्राप्त किया गया था। पीएम आवास योजना शहरी की भागीदारी में किफायती आवास घटक के अंतर्गत स्वीकृत 29 हजार 142 आवासीय इकाईयों में से 18 हजार 131 आवासीय इकाईयों को पूर्ण किया गया था। इनमें से मार्च 2025 तक शहरी स्थानीय निकायों द्वारा मोर मकान मोर आस योजना में 10 हजार 903 आवासीय इकाईयां आवंटित की गई। योजना के तहत आवंटित आवासों के लिए हितग्राहियों का अंशदान प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी में 16 प्रतिशत (0.75 लाख) के स्थान पर 68 प्रतिशत (3.25 लाख) था। इस प्रकार, अंशदान का अधिक हिस्सा हितग्राहियों से वसूल किया गया और राज्य के हिस्से के अंशदान का भार भी हितग्राहियों पर स्थानांतरित कर दिया गया। 11 शहरी स्थानीय निकायों में, मार्च 2025 तक 10.903 हितग्राहियों को आवासीय इकाईयों के आवंटन के विरुद्ध 187.76 करोड़ रुपए का अतिरिक्त अंशदान प्राप्त किया गया।

स्वामी, मुद्रक एवं प्रकाशक श्री सुकांत राजपूत द्वारा ए.आर. प्रिंटर्स, निरंकारी फर्नीचर के पीछे, पंडरी रायपुर से मुद्रित एवं शहरसत्ता, एस-15 प्रियदर्शिनी नगर, सेक्टर 1, मातृ-पितृ छाया अपार्टमेंट, रायपुर (छ.ग.),
मोबाईल नं. 98271-81979, फोन नं. 0771-3158142, संपादक - सुकांत राजपूत (पीआरबी एक्ट के तहत समाचार के लिए जिम्मेदार), महाप्रबंधक - प्रदीप चंद्रवंशी (मो. 70006-81023)। डाक पंजीयन - CG/RYP/DN/70/2025-27